खास बात

"मौत अगर आसान नहीं, जीना भी आसान नहीं। मौत को मुश्किल जानने वालों, जीना मौत से मुश्किल है ।।"
- जगन्नाथ 'आजाद'

।। श्री हरि शरणम् ।।

रायसेन से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

अमृत दर्शन

RNI No. MPHIN/2012/43555

वर्ष - 13 अंक - 254

रायसेन
शनिवार, 14 मार्च 2026

● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 1 रुपया

Website : www.amritdarshan.com

रायसेन, नर्मदापुरम एवं भोपाल से प्रकाशित

केंद्र सरकार ने कहा घरेलू गैस की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं

जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सरकार ने आज देशवासियों को आश्वस्त किया कि देश की रिफायनरियों में कच्चे तेल से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने की कोई भी संभावना नहीं है इसलिए आम जनों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जमाखोरी करने को चेताया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उच्चपदस्थ सूत्रों ने यहां संवाददाताओं से कहा कि देश में एलपीजी की आपूर्ति पर पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण कुछ असर हुआ है लेकिन भारत में स्थिति तेल रिफायनरियों में क्षमता वृद्धि के उपाय किये गये हैं और जल्द ही बाज़ार में उपलब्धता बढ़ेगी। सूत्रों के अनुसार देश की रिफायनरियों में एलपीजी के उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके और बढ़ने की संभावना है।

सूत्रों ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट के नाम पर देश में जो भी वितरक कृत्रिम संकट बता कर जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर सरकार की पैनी नज़र है और उन्हें पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल व्यावासयिक सिलेंडरों की आपूर्ति नियंत्रित की है और प्राथमिकता के आधार पर उनके वितरण का निर्णय करने का अधिकार राज्यों को दिया है।

सूत्रों ने बताया कि भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है जो अपनी एलपीजी खपत का लगभग 55-60% हिस्सा मुख्य रूप से खाड़ी देशों- कतर एवं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से सीधे आयात करता है, जबकि शेष 40-45% घरेलू स्तर पर रिफाइनरियों में कच्चे तेल के शोधन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। हाल ही में सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों को आदेश दिया है। वैश्विक आपूर्ति में बाधा का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत एलपीजी का लगभग 29-34% हिस्सा कतर से आयात करता है और कतर के बाद यूएई लगभग 26% की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हाल के वर्षों में, भारत ने कतर से सालाना 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी का आयात किया है, जिसकी कीमत 4 अरब डॉलर से अधिक है। 2024 में, भारत और कतर ने 2048 तक सालाना 75 लाख टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के लिए एक बड़ा समझौता भी किया है। भारत की आयातित एलपीजी का अधिकांश भाग होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है जिसे ईरान ने बाधित कर रखा है।

सूत्रों ने कहा कि भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति का कोई संकट नहीं है। भारत रूस समेत 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल की खरीद करता है। भारत ने अपनी रिफायनरियों से कहा है कि वह कच्चे तेल के शोधन में उप उत्पादों में एलपीजी को प्राथमिकता दें और उनका उत्पादन बढ़ाएं ताकि बाहर से आने वाली एलपीजी की कमी की यथासंभव भरपाई हो सके।

एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष की नारेबाजी वित्त मंत्री बोलीं- मुश्किल समय में साथ खड़े हों

संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन, शुक्रवार को भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। लोकसभा में हंगामे का कारण पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक फिर से कार्यवाही स्थगित की गई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।

दैनिक मांग 20 लाख बढ़ी, केंद्र ने कहा पैनिक बुकिंग न करें

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और नागरिकों को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर पैनिक बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार सामान्य समय में जहां एलपीजी की औसत दैनिक बुकिंग 55.7 लाख रहती थी, वहीं हाल के दिनों में यह बढ़कर 75.7 लाख तक पहुंच गई है, जो पैनिक बुकिंग का संकेत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन 5 मार्च की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है और घरों तक गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक बुकिंग से बचें। उन्होंने बताया कि भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन है और देश पेट्रोल तथा डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

संस्कृति विभाग के माध्यम से भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजन होंगे

नवरात्रि से पहले लाड़ली बहनों को तोहफा सीएम ने खातों में ट्रांसफर किए 1836 करोड़

भोपाल ■ प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवरात्रि से पहले प्रदेश की लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात देते हुए लाड़ली बहना योजना की 34वीं किश्त जारी की। ग्वालियर जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500 रुपये की दर से कुल 1836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 121 करोड़ रुपये की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और कन्या पूजन से हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाओं पर पुष्पवर्षा की और हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, स्व-सहायता समूहों के चेक तथा मुद्रा योजना के चेक भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रदेश की बहन-बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि जून 2023 से फरवरी 2026 तक योजना की 33 किश्तों के माध्यम से 54,140 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नवंबर 2025 से मासिक सहायता में 250 रुपये की वृद्धि के बाद अब पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लाड़ली बहना योजना को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि महिलाओं को कौशल उन्नयन, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भितरवार क्षेत्र में 122 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इसमें 40 करोड़ रुपये की लागत से सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण और एक नए पुल का भूमिपूजन शामिल है। डबरा के जौरासी गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक के दूसरे चरण के लिए 12.5 हजार करोड़ रुपये के कार्य का भूमि पूजन प्रस्तावित है। कुलैथ, डबरा और मुरार में 50-50 सीट के बालक-बालिका छात्रावास बनाए जा रहे हैं। आईएसबीटी के पास 7 करोड़ रुपये की लागत से श्रमिक विश्रामगृह का निर्माण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज बरही के किसान सम्मेलन में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार 14 मार्च को कटनी जिले के बरही (विजयराघवगढ़) में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 243.22 करोड़ रुपये के निर्माण व विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बरही के बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे और बरही के बड़े तालाब से श्री विजयनाथ धाम मंदिर प्रांगण सभा स्थल तक आभार रैली में शामिल होंगें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसान सम्मेलन में कृषि एवं उससे संबंधित विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, सुपर सीडर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्व-सहायता समूह बैंक योजना और रिस्पोंसिबल टूरिज्म होम स्टे से लाभान्वित 7 हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे।

लिखी जा रही विकास की नई इबारत

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बहनों को प्रतिमाह 3000 रुपये तक देने का लक्ष्य रखा गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और किसानों व महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं

सीएम ने यह घोषणाएं भी की

- भितरवार के पीएचसी को सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा
- घाटीगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन होगा
- भितरवार और घाटीगांव में आईटीआई केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- मां शबरी मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि सर्वे कराया जाएगा

अंतर्मना उवाच

सबसे अच्छा क्या है... समय। सबसे बुरा क्या है... समय। फिर दोनों में अंतर क्या है...? - वक्त का।

कल तक रजाई कंबल सगे लगते थे और आज कूलर पंखे अपने लगने लगे हैं। इसलिए ***कोई भी कठिन समय जीवन का अंतिम सत्य नहीं होता।***

मित्रों..! जीवन में आने वाली कोई भी बाधायें, रुकावटें नहीं होती। वे हमें कुछ नया सीखने और सिखाने के लिए प्रेरणास्पद होती है। *जब भी हम कठिन वक्त के दौर से गुजरने से कतराते हैं या बचना चाहते हैं, तो हम अपने विकास का एक बड़ा अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं चुनौतियों का साहस से सामना करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी सोच और सोचने की क्षमता दोनों मजबूत होने लगती है।*

सच तो यह है कि -- ***हर समस्या के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है, एक समाधान भी छिपा होता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और सही दिशा बतलाता है...!!!***

प्रतापगढ़ (राज) में मंगल बिहार में तपती धूप में दोपहर की सामायिक (जप, तप, ध्यान, आराधना) करते अंतर्मना गुरुदेव 108 प्रसन्न सागरजी महाराज

■ अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज

प्राकृतिक आपदा प्रभावित 6 राज्यों को दी 1,912 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान 'मोंथा' से प्रभावित छह राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जाएगी।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस राशि में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़, गुजरात को 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़, नगालैंड को 158.41 करोड़ और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन होगी। सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर संभव मदद प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

मप्र में जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, अब 77,662 मिलेंगे

सीनियर रेजिडेंट के लिए 90,803 रुपए तय; हड़ताल के 4 दिन बाद आदेश जारी

भोपाल ■ प्रतिनिधि

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह संशोधन जारी किया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

सरकार ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की है। जूनियर डॉक्टरों को अब 77,662 रु. मिलेंगे, जबकि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 90,803 रु. तय किया गया है। हड़ताल के चार दिन बाद आदेश जारी किया गया है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और काम करने वाले पीजी छात्रों, इंटर्न और सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को सीधा फायदा होगा। सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह जूनियर डॉक्टरों द्वारा स्टाइपेंड में संशोधन की मांग को लेकर हाल ही में की गई हड़ताल के बाद उठाया गया है।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जूनियर डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में वे न केवल अपने चिकित्सा प्रशिक्षण को पूरा करते हैं, बल्कि मरीजों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

भारत ने दिया करारा जवाब, कहा- पूरी दुनिया को पता है...

कनाडा के साथ यूरेनियम डील पर पाक पीटने लगा माथा: जायसवाल

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत ने पाकिस्तान द्वारा भारत-कनाडा यूरेनियम आपूर्ति समझौते को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु अप्रसार के मामले में भारत की साख बेदाग है और पाकिस्तान अपने खराब रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने के लिए हास्यास्पद बयान दे रहा है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों का भी खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'पाकिस्तान द्वारा दिया गया यह बयान पूरी तरह हास्यास्पद है। परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत की साख वैश्विक समुदाय के लिए स्पष्ट है। जबकि गुप्त परमाणु प्रसार के इतिहास वाला कोई देश ऐसे बयान कैसे दे सकता है, यह अपने खराब रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है।' गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में कनाडा के साथ 2.6 अरब डॉलर का दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है।

ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने को लेकर विपक्ष की तरफ से दोनों सदनों में दिया गया प्रस्ताव

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव 10 पन्नों का है जिसमें 7 कारण गिनाए गए हैं, जिनके आधार पर ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में दिए गए नोटिस में सदन के 130 सदस्यों और राज्यसभा में दिए गए नोटिस में 63 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। नियमों के कारण लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इराक में अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत: सेंटकॉम

लंदन/वाशिंगटन ■ एजेंसी

इराक में अमेरिकी सेना का एरियल रीफ्यूलिंग विमान केसी-135 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चार सैन्य कर्मियों की मौत हो गयी। अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में शामिल दो बोइंग कंपनी के केसी-135 विमानों में से एक क्रैश हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित उतरा। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह घटना न तो अपनी तरफ से हुई गोलीबारी के कारण हुई और न ही दुश्मन की गोलीबारी से।

अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पोस्ट में कहा, '12 मार्च की दोपहर लगभग 2 बजे पश्चिमी इराक़ में एक अमेरिकी केसी-135 रीफ़्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी रहने के बीच विमान में सवार चालक दल के छह सदस्यों में से चार की मौत हो गई। इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है।' मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इराक में इस्लामिक रेज़िस्टेंस नाम के संगठन ने इस विमान पर हमले की ज़िम्मेदारी ली है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसे दुश्मन का हमला नहीं माना है और बताया है कि विमान वहां गिरा जहां 'दोस्त देश का एयर स्पेस' था। रीफ़्यूलिंग विमान लड़ाकू विमान में हवा में ही ईंधन भरता है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम (एबीसी) और अमेरिकी वेबसाइट फॉक्स 8 के अनुसार पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना का एक एरियल रीफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार चार सैन्य कर्मियों की मौत हो गई।

उड़ता तीर

'अफवाह फैला रही कांग्रेस'; पीएम ने असम दौरे पर पंडित नेहरू का जिक्र कर नीतियों पर बोला हमला

पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 4 लाख करोड़ ट्रांसफर किए

गुवाहाटी ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने के अलावा आज पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी ट्रांसफर की। पीएम मोदी ने टर्मिनल, जेटी से लेकर सड़कों से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सवा चार लाख करोड़ रुपये की राशि जमा हो जाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत होने के बाद कांग्रेस वाले कहते थे कि आज भले ही पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद पैसे सरकार को वापस करने पड़ेंगे। ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि ये योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पर्याय बन चुका है।

पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर भी जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार किसानों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में भाजपा-एनडीए की सरकार ने आत्मनिर्भरता को लेकर भी अहम फैसले लिए हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाली लड़ाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले किसानों पर सीधा असर पड़ता था। कभी खाद महंगी होती थी, कभी डीजल और ऊर्जा पर खर्च बढ़ जाता था।ऐसा इसलिए क्योंकि दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा था। आज सरकार कोशिश इस बात की कर रही है कि डीजल पर खर्च को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने सौर ऊर्जा का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अन्नदाता को ऊर्जा-दाता बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

सरेंडर करने वाला है ईरान, जी7 की बैठक में ट्रंप का बड़ा दावा; 'हमने कैंसर को खत्म कर दिया'

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 देशों के नेताओं के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में दावा किया है कि ईरान की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है और वह अब आत्मसमर्पण के करीब पहुंच गया है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध का परिणाम अब लगभग तय हो चुका है। हालांकि इस बयान पर व्हाइट हाउस की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई। बताया गया है कि बुधवार को जी-7 देशों के नेताओं के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान Operation Epic Fury का भी उल्लेख किया।

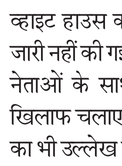

ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लगाए जाएंगे एचपीवी के टीके

खंडवा ■ निसं

महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उद्देश्य से एचपीवी टीकाकरण अभियान इन दिनों जारी है। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को एचपीवी के टीके लगाये जा रहे हैं। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी बालिकाओं को अपने निकटतम टीकाकरण केन्द्र पर ले जाकर एचपीवी का टीका अवश्य लगवाएं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च को खण्डवा ब्लॉक के बोरगांवखुर्द कन्या छात्रावास में एचपीवी टीके लगाए जाएंगे। खंडवा विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अटूट भिखारी का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी जावर में किया जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को ही ग्राम पंचायत बडगांव माली का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी सिंहाडा में, ग्राम पंचायत बेनपुरा कुरवाड़ा का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी अमलपुरा में, ग्राम पंचायत पीपलकोटा का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी सहेजला में किया जाएगा।

पंधाना विकासखंड में 14 मार्च को एचपीवी टीकाकरण घाटाखेड़ी, बोरगांव, कोहदड़, पिपलौद, सिंगोट, दीवाल, गांधवा व गुड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंधाना में किया जाएगा। हरसूद विकासखंड के अंतर्गत 14 मार्च को एचपीवी टीकाकरण सिविल अस्पताल हरसूद में किया जाएगा। किल्लौद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जैतापुर कला का एचपीवी टीकाकरण सीएचसी किल्लौद में किया जाएगा। छैगांवमाखन विकासखंड के अंतर्गत 14 मार्च को एचपीवी टीकाकरण ग्राम पंचायत सैयदपुर, संगवाड़ा, सिलोदा एवं सिरसौद का टीकाकरण सीएचसी छैगांवमाखन में किया जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को ही ग्राम पंचायत टीटगाँव एवं टोकरखेड़ा का टीकाकरण पीएचसी चिचगोहन में किया जाएगा।

पुनासा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोदवार का एचपीवी टीकाकरण सीएचसी मूंदी में किया जाएगा। इसके अलावा 14 मार्च को ही ग्राम पंचायत अंजनिया कला का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी जामकोटा में, ग्राम पंचायत भगवानपुरा का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी बीड़ में, ग्राम पंचायत सवतापुर का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी रिछफल में, ग्राम पंचायत डुडगांव का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी मोहना में, ग्राम पंचायत नेतनगांव एवं गुंजली का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी सुलगांव में, ग्राम पंचायत अटूटखास का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी बोराडीमाल में तथा ग्राम पंचायत हरवंशपुरा एवं घोंघनपुरा का एचपीवी टीकाकरण पीएचसी गोल में किया जाएगा।

खालवा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटवारिया माल एवं सावलीखेड़ा का एचपीवी टीकाकरण सिविल अस्पताल खालवा में किया जाएगा।

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के पहले दिन सर्वर फेल

आधार ओटीपी के बाद 'डाटा एरर' से नहीं भर पा रहे फॉर्म

बुधनी ■ निसं

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पहले ही दिन तकनीकी समस्याएं सामने आ गईं। सर्वर में गड़बड़ी और आधार सत्यापन में आ रही त्रुटियों के कारण आवेदक दिनभर परेशान होते रहे और कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए। जानकारी के अनुसार, जब आवेदक आरटीई पोर्टल पर आवेदन करते समय आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन करते हैं, तो

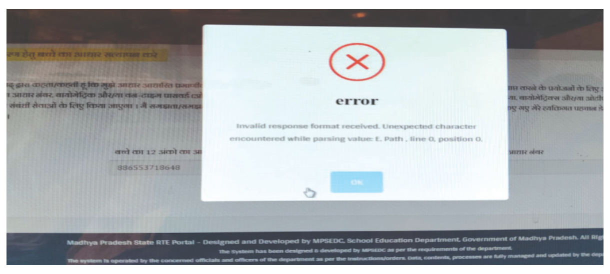

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन ओटीपी दर्ज करने के बाद सिस्टम में 'आधार डाटा एरर' का संदेश आ रहा है। इस समस्या के कारण आवेदन फॉर्म आगे नहीं खुल पा रहा है।

तकनीकी खामी के चलते कई अभिभावक सुबह से ही एमपी ऑनलाइन और साइबर कैफे के चक्कर लगाते नजर आए। ऑपरेटरों का कहना है कि सर्वर या आधार वेरिफिकेशन में तकनीकी दिक्कत के कारण फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे हैं।

अभिभावकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द तकनीकी समस्या का समाधान करे, ताकि आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

संक्षिप्त समाचार

एलपीजी सिलेंडर के अवैध भंडारण व कालाबाजारी रोकने हेतु जांच दल गठित

खण्डवा। आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति और विपणन केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किया जाना है। कमर्शियल सिलेंडर अब सिर्फ शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय संस्थानों को ही डिलीवर किया जाएगा। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 25 दिवस के अंतराल पर ही बुकिंग की अनुमति रहेगी। शासन के निर्देशों के पालन में एलपीजी सिलेंडर की अवैध भंडारण, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से तहसीलवार जांच दलों का गठन किया गया है। जारी आदेश अनुसार इन जांच दलों में सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को शामिल किया गया है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि ये दल सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं एसडीओपी के निर्देशन में कार्यवाही करेंगें। इन दलों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण समय समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दलों को निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उपयोग पाया जाने पर जब्ती की कार्यवाही करें।

पात्र परिवारों को मार्च व अप्रैल माह का खाद्यान्न एक साथ वितरित होगा

खण्डवा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से गरीब पात्र परिवारों को नि :शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जिला आपूर्ति ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार इस बार मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री एक साथ वितरित की जाएगी। इसके लिए हितग्राही को उचित मूल्य दुकानों पर लगायी गयी पीओएस मशीन से एक बार मार्च माह के लिए तथा दूसरी बार अप्रैल माह के लिए अर्थात कुल 2 बार अपना अंगूठा मशीन पर लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। दो बार अंगूठा लगाने के बाद उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा हितग्राही को दोनो माहों की राशन सामग्री एकसाथ दी जावेगी। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि उचित मूल्य दुकान पर जाकर दो बार बॉयोमेट्रिक सत्यापन अर्थात अंगूठा लगाकर मार्च एवं अप्रैल दोनो माह का खाद्यान्न प्राप्त करें तथा मशीन से प्रिंट 2 पावती भी जरूर प्राप्त करें।

साईकृपा कॉलोनी में रंगारंग बाना कार्यक्रम आयोजित होगा

इंदौर। इंदौर साईकृपा कॉलोनी, शिव मंदिर परिसर में 14 मार्च, शनिवार को रंगारंग बाना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रंगारंग बाना कार्यक्रम शाम 4 :30 बजे से रात 9 :00 बजे तक चलेगा नेहा कानुनगो ने कार्यक्रम की जानकारी दी कार्यक्रम की शुरुआत हाई टी से होगी, जिसके बाद मस्ती भरा रंगारंग बाना प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में सखियों और भाइयों के ग्रुप गेम्स, सखियों का रैम्प वॉक और कपल गेम्स शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

जबलपुर में गैस सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी

क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, मकान से 46 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर जब्त

जबलपुर ■ निसं

जबलपुर में अवैध गैस सिलेंडर की बिक्री और भंडारण के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आधारताल थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए एक मकान से 46 घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई महाराजपुर इलाके में रहने वाले प्रदीप साहू (55) पिता रूपलाल साहू निवासी जगदंबा कॉलोनी के यहां की गई। आरोपी के कब्जे से कुल 46 सिलेंडर मिले, जिनमें 8 भरे हुए, 32 खाली, 4 कमर्शियल और 2 छोटे सिलेंडर (भारत और इंडेन कंपनी) के बताए जा रहे हैं।

लंबे समय से कर रहा था कालाबाजारी: जानकारी के अनुसार प्रदीप साहू लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री और कालाबाजारी में लिप्त था। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके परिसर पर दबिश दी और बड़ी संख्या में सिलेंडर बरामद किए।

कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार, पटवारी और खाद्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सिलेंडर जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई।

अफवाहों पर ध्यान न दें: एसपी: इस बीच संपत उपाध्याय ने जिले में घरेलू गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई लगातार जारी है। एसपी के मुताबिक कुछ लोग अफवाहों के कारण सिलेंडर का अनावश्यक भंडारण कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि बुकिंग पोर्टल पर अधिक लोड होने के कारण कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जा रहा है।

कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई: एसपी ने कहा कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने या लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं गैस की अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें, ताकि संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा सके।

एसडीएम सिवनी मालवा ने गैस वितरकों की बैठक ली

सिवनी मालवा। सिवनी मालवा अंतर्गत एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था की समीक्षा हेतु गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा डॉ बबीता राठौर द्वारा अनुविभाग कार्यालय में गैस वितरकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेएसओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संबंधित गैस एजेंसियों से उपलब्ध स्टॉक, मासिक सप्लाई तथा घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं की जानकारी प्राप्त की गई। एसडीएम डॉ राठौर ने सभी वितरकों को शासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति केवल अस्पतालों एवं शासकीय संस्थाओं को ही की जाए। इसके अतिरिक्त सभी गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण निर्बाध एवं सुचारू रूप से करने के लिए कहा गया। एसडीएम डॉ राठौर ने कहा कि गैस वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दीपक एडवरटाइजिंग का इंदौर में नया स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑफिस

इंदौर ■ निसं

मध्य भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी दीपक एडवरटाइजिंग अपनी सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्साहित है। दीपक एडवरटाइजिंग का हेड ऑफिस अब स्थानांतरित होकर जेठा वन, सेकंड फ्लोर, ए-13, सिल्वर स्प्रिंग बिजनेस पार्क, डीमार्ट के सामने, बाय पास पर आ गया है। तीन ओर से ग्रीनरी से घिरा ऑफिस अधिक विशाल, आधुनिक और रचनात्मक तरीके से बनाया गया है, जो क्रिएटिव कार्य करने के लिए सही वातावरण देता है।

नवीनतम तकनीक और डिजाइन से लैस यह स्पेस एजेंसी की इनोवेटिव कैंपेन और ब्रांड बिल्डिंग क्षमताओं को नई गति देगा।

दीपक जेठा, मैनेजिंग डायरेक्टर, दीपक एडवरटाइजिंग एजेंसी ने कहा, 'यह अपग्रेड हमारी ग्राहक-केंद्रित प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।मैं ग्राहको, मीडिया और टीम के विश्वास के लिए कृतज्ञ हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है की हम सब साथ मिलकर नई सफलताओं की ओर बढ़ेंगे।' उल्लेखनीय है की दीपक एडवरटाइजिंग एजेंसी ने 190 से अधिक मीडिया और क्रिएटिव पुरस्कार जीते है।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय क्रिएटिव अवॉर्ड्स जीतने वाले और ग्राहको के दिल तक सीधे पहुँचने वाले विज्ञापन समाधानों के लिए जाने वाली दीपक एडवरटाइजिंग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े रिटेल, लाइफस्टाइल एवम प्राइवेट कंपनियों को सेवा प्रदान कर रही है।

ग्राम चौतलाय में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग

प्रशासन व ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा नुकसान टला

सिवनी मालवा ■ निसं

क्षेत्र के ग्राम चौतलाय में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने तुरंत जिला कलेक्टर एवं एसडीएम से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर अग्निशमन वाहन भेजा गया, जिससे आग पर शीघ्र नियंत्रण पाने में सहायता मिली।

सूचना प्राप्त होते ही विधायक प्रेमशंकर वर्मा स्वयं भी ग्राम चौतलाय पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम के जागरूक ग्रामीणों ने भी तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने में प्रशासन का सहयोग किया। ग्राम सरपंच रामजीवन साध ने बताया कि आग से लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। इसमें संतोष कुमार साध की लगभग 2.3 एकड़, रामकृष्ण साध की लगभग 3 एकड़ तथा रामभरोस लोवंशी की करीब 4 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है।

ग्रामीणों ने स्प्रे पंप, गांव के पानी के टैंकर तथा अग्निशमन वाहन की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। सैकड़ों ग्रामीणों की सक्रियता और प्रशासन की तत्परता से आग पर शीघ्र काबू पा लिया गया, जिससे अधिक क्षति होने से बचाव हो सका। मौके पर उपस्थित पटवारी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने एवं फसल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को शासन की ओर से नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि फसल के मौसम में विशेष सावधानी बरतें।

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के पहले दिन सर्वर फेल, आधार ओटीपी के बाद 'डाटा एरर' से नहीं भर पा रहे फॉर्म

बुदनी। शहर के प्राईवेट स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन लेने के लिए पहले ही दिन बच्चों के परिजनों को परेशान होना पड़ा। 13 मार्च शुक्रवार से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पहले ही दिन सर्वर पर तकनीकी समस्याएं के कारण बच्चों के फार्म नहीं भरा सके। सर्वर में गड़बड़ी और आधार सत्यापन में आ रही त्रुटियों के कारण आवेदक दिनभर परेशान होते रहे और कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए। जानकारी के अनुसार, जब आवेदक आरटीई पोर्टल पर आवेदन करते समय आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन करते हैं। इससे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन ओटीपी दर्ज करने के बाद सिस्टम में 'आधार डाटा एरर' का संदेश आ रहा है। इस समस्या के कारण आवेदन फॉर्म आगे नहीं खुल पा रहा है। टेक्निकल एरर के कारण सर्वर नहीं चला जिससे बच्चों के आवेदन पहले दिन ही भरने में परेशानियों का सामना पेरेंट्स को करना पड़ा। पेरेंट्स सुबह से ही एमपी ऑनलाइन और सीएससी सेंटर के के चक्कर लगाते नजर आए। ऑपरेटरों का कहना है कि सर्वर या आधार वेरिफिकेशन में तकनीकी दिक्कत के कारण फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे हैं।

बाहुबली एग्रो इंडस्ट्रीज का भव्य शुभारंभ

खरगोन ■ निसं

औद्योगिक क्षेत्र औरंगपुरा में स्थापित बाहुबली एग्रो इंडस्ट्रीज का शुभारंभ खरगोन विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार एवं भगवानपुरा विधायक श्री केदार डाबर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक केदार डाबर ने बालकृष्ण पाटीदार(कान्हा)को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक किसान के रूप में नवाचार और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर सफलता प्राप्त की है और अपने अनुभव के आधार पर इस उद्योग की स्थापना की है, जो क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायक है।

वहीं विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बाहुबली एग्रो इंडस्ट्रीज को निमाड़ क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए किसानों से खेती को उद्योग के रूप में अपनाने का आह्वान किया। बाहुबली एग्रो के डायरेक्टर बालकृष्ण पाटीदार (कान्हा)ने बताया कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से कृषि उपज का मल्टी ग्रेडिंग प्रोसेस किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा।

कार्यक्रम में संतोष पाटीदार बलवाड़ी, श्याम मित्तल केली, सोहन पाटीदार डालकी, शांतिलाल पाटीदार, गोपाल मित्तल, मनीष पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसान बंधु और पत्रकार मौजूद रहे।

गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर नगर कांग्रेस का ज्ञापन, समस्या समाधान की मांग

सिवनी मालवा ■ निसं

नगर कांग्रेस ने रसोई गैस की बढ़ती किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार नितिन झोड़ को सौंपकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। नगर कांग्रेस का कहना है कि सिवनी मालवा तहसील सहित पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नगर कांग्रेस के अनुसार गैस एजेंसियों में ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए बार-बार एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से कई परिवारों की रसोई तक प्रभावित हो रही है।

नगर कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भी बाजार में भारी कमी है, जिसके कारण होटल, ढाबे, चाय-नाश्ते की दुकानों सहित छोटे व्यापारियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों को गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तत्काल सुचारु रूप से शुरू की जाए तथा घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही नगर कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि यदि कहीं गैस एजेंसियों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी की जा रही हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नगर कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आम जनता के हित में आंदोलन किया जाएगा। स्वदेश शर्मा नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, हैरिसन स्वामी अध्यक्ष युवक कांग्रेस, विकास पाठक,हरिओम रघुवंशी, दीपक गोस्वामी, प्रशांत रघुवंशी, हिमांशु मानिक, अनुराग लोवंशी हर्षित राठौर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तनाव प्रबंधन विषय पर 'मनोबल' सत्र आयोजित

सिवनी मालवा ■ निसं

नगर के कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी मालवा में शुक्रवार को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए तनाव प्रबंधन विषय पर 'मनोबल' जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के समय होने वाले मानसिक दबाव से निपटने के उपायों की जानकारी देना रहा।

कार्यक्रम वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. के. यादव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक डॉ. जया कैथवास ने बताया कि परीक्षा काल में तनाव प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर आधारित 'मनोबल' सत्र 13 मार्च से 17 मार्च तक आभासी माध्यम से आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने के उपायों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता डॉ. तन्मय जोशी, सहायक प्राध्यापक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक तनाव से निपटने की मनोवैज्ञानिक युक्तियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि समय का उचित नियोजन, यथार्थ लक्ष्य निर्धारण, नियमित शारीरिक व्यायाम तथा सकारात्मक आत्मसंवाद तनाव को कम करने में सहायक होते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान थोड़े-थोड़े अंतराल लेने, पर्याप्त विश्राम करने तथा ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। साथ ही टहलना, दौड़ना अथवा व्यायाम करना मन को शांत रखने और एकाग्रता बढ़ाने में उपयोगी बताया।

हिंदू नववर्ष विक्रम संवत् 2083 की शुरुआत 19 मार्च से

इस बार नवसंवत्सर का राजा बृहस्पति और नाम होगा रौद्र, मंत्री रहेगा मंगल

गुरु-बृहस्पति से सोना-चांदी में उतार चढ़ाव, वर्षा अच्छी होगी

भोपाल ■ निसं

हिंदू नववर्ष विक्रम संवत् 2083 की शुरुआत 19 मार्च से होगी। यह नव संवत्सर का नाम रौद्र कहलाएगा। इसके राजा देवगुरु बृहस्पति और मंत्री मंगल होंगे। ब्रह्मांडीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा। बृहस्पति के कारण सोने-चांदी के भावों में भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। रौद्र संवत्सर को उग्र, परिवर्तनशील और तीव्र प्रभाव देने वाला माना है। वर्षभर प्राकृतिक घटनाओं में असंतुलन की स्थिति बन सकती है। कहीं अत्यधिक तो कहीं अल्प वर्षा, भूकंप और आंधी-तूफान जैसी घटनाएं संभव हैं। वातावरण में उष्णता बनी रह सकती है।

पं. अमर डब्बावाला के मुताबिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर सृष्टि का आरंभ माना है ज्योतिष शास्त्र एवं पंचांग की गणना के अनुसार इस बार गुरुवार के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इस दृष्टि से गुरुवार के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होने से वर्ष के राजा बृहस्पति होंगे। नवग्रह में बृहस्पति को गुरु पद की संज्ञा दी है और वर्तमान में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचरस्थ है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा को गुरुवार होना भारत सहित मध्यप्रदेश के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि आंतरिक संयोजन के संबंध में चिंतन की आवश्यकता रहेगी।

कृषि के साथ धन-धान्य का होगा भंडारण: पं. डब्बावाला के मुताबिक ग्रहों की दृष्टि संबंध से समय पर दृष्टि एवं कृषि का संबंध अनुकूल रहेगा। हालांकि समय-समय पर कहीं-कहीं अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। फिर भी परिणाम में अनुकूलता का योग है। वर्ष के आरंभ में मीन लग्न में सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि इन चार ग्रहों के साथ ही बृहस्पति के वर्गोत्तम एवं केंद्र योग में प्रबल भूमिका होने से प्राचीन वैभव पुनः प्राप्त होने के साथ-साथ आमजन मानस में धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। साथ ही परम सत्ता का अनुभव आम जनमानस कर सकेंगे।

मंत्री मंगल होने से रोग बढने के आसार: पं. मीतेश पांडे ने बताया राजा बृहस्पति होने से प्रभावों की तीव्रता सीमित रहेगी और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। मंत्री मंगल होने से अपराध और रोगों में वृद्धि संभव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। बृहस्पति के प्रभाव से कृषि, दुग्ध उत्पाद और खाद्यान्न उत्पादन बेहतर रहने के योग हैं। कृषि, राजनीति और महंगाई-कृषि क्षेत्र में मिला-जुला प्रभाव रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी फसल, तो कुछ स्थानों पर फसल हानि हो सकती है। जब राजा गुरु हो तो उस वर्ष पृथ्वी लोक पर अच्छी वर्षा की संभावना रहती है। मीन लग्न में नए साल की शुरुआत, लग्न का अधिपति भी बृहस्पति- पं. मनीष त्रिवेदी के अनुसार ज्योतिष के गणितीय पक्ष में सूर्य का उदय और वर्ष का लग्न किस क्रम से शुरू हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान दिया है। यदि यह अनुकूल परिस्थितियों में है तो वर्ष पर्यंत सकारात्मकता, उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस क्रम में सौम्य लग्न की स्थिति अनुकूल रहती है। संयोग से बृहस्पति का वार बृहस्पति का लग्न और बृहस्पति की पांचवीं, सातवीं, नौवीं दृष्टि सहयोग के साथ सकारात्मकता दर्शा रही है।

स्मार्ट मीटर लगाने दादागीरी पर उतारू बिजली कंपनियां

एक साथ थमाए जा रहे हैं हजारों रूपये के बिल

फिर स्मार्ट मीटर लगाने बनाते हैं दबाव और मना करने पर काट देते हैं बिजली

भोपाल ■ निसं

बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ दादागीरी पर उतारू हैं। स्मार्ट मीटर लगाने जहां हजारों के मनमाने बिल थमाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी दुरूस्त कराने पहुंचे लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बनाया जाता है। इतना ही नहीं उपभोक्ता के इंकार करने पर कनेक्शन काटकर परेशान करने से बाज नही आ रहे हैं।

दरअसल सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का है। उद्देश्य यह भी है कि बिजली बिलिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। बावजूद इसके इनमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे तरीके लोगों की परेशानी का कारण बन गये हैं। इससे न केवल भारी भरकम बिल बर्दाश्त करना पड़ रहा है बल्कि, अधिकारियों की दादागीरी से भी दो-चार होना पड़ रहा है। जिसमें बिल जमा होने के बाद भी कनेक्शन काट कर अंधेरे में रहने के लिये मजबूर करना भी शामिल है।

समय पर रीडिंग नहीं, एक साथ भेज रहे 4 माह का बिल: उपभोक्ताओं का आरोप है कि जिन घरों में पहले से मीटर लगे हैं, उन्हें बदलने के लिये बिजली कंपनी के कर्मचारी महीनों रीडिंग के लिये नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद यूनिट के आधार पर 4-4 माह के एवरेज बिल थमा दिये जाते हैं। इसके बाद ना तो बिल में रियायत दी जाती है और न ही अधिकारी शिकायत पर किसी तरह की सुनवाई ही करते है। जबकि मीटर सही रीडिंग देते हुए काम कर रहे हैं। अशोका गार्डन क्षेत्र से जुड़े ऐसे ही मामले में औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय अधीक्षण यंत्री धानेंद्र तिवारी ने इसके पीछे तर्क दिया है कि पुराने मीटर धीमी रफ्तार से चलते हैं और सही बिल नहीं देते हैं।

विरोध पर मनमानी पड़ रही भारी: बिजली कंपनियों के जबरिया रूख के खिलाफ लोग सडक़ पर उतर रहे हैं। मप्र बिजली उपभोक्ता ऐसोसियेशन इसके लिये जन जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहा है। बावजूद इसके कंपनियों की मनमानी रूकने का नाम नहीं ले रही है।

संक्षिप्त समाचार

भोपाल नगर निगम में लोकायुक्त का धावा, फर्जी बिलों के खेल से हड़कंप

भोपाल। राजधानी के नगर निगम दफ्तर में लोकायुक्त की टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक कर खलबली मचा दी है। आईएसबीटी स्थित दफ्तर और सर्वर रूम को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि कर्मचारियों ने फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों का घोटाला किया है। लोकायुक्त की टीम अब सर्वर से डिजिटल डेटा रिकवर कर रही है, जिससे निगम के कई सफेदपोशों और भ्रष्ट मुलाजिमों के चेहरे बेनकाब होने की आशंका है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद निगम गलियारों में सन्नाटा पसरा है।

पुलिस ने मंडप से उठा लिया गैंगस्टर दूल्हा

भोपाल। राजधानी में एक फिल्मी ड्रामा देखने को मिला, जहां हाथों में मेहंदी और चेहरे पर हल्दी लगाए एक दुल्हन थाने पहुंच गई। मामला इलीगल गैंग के सरगना आकाश उर्फ भूरा हड्डी का है, जिसे पुलिस ने शादी के मंडप से ऐन वक्त पर गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर की दुल्हन सीमा ने टीआई से फरियाद की, कि या तो दूल्हे को दो घंटे की मोहलत दें या कस्टडी में ही फेरे करवा दें। हालांकि, पुजारी के अपहरण और 8 लाख की फिरौती के आरोपी इस बदमाश को न तो पुलिस और न ही कोर्ट से कोई राहत मिली।

कांग्रेसियों ने नाले में खड़े होकर घेरी केंद्र सरकार

भोपाल। राजधानी के प्रभात चौराहे पर आज युवा कांग्रेस ने गैस किल्लत के खिलाफ अनोखा मोर्चा खोला। अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ता गंदे नाले में उतरे और नरेन्दर सरेंडर गैस सिलेंडर सेंटर शुरू कर विरोध जताया। प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने तो यह कह डाला कि ना नाले से गैस निकली, ना जनता की परेशानी कम हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इजरायल-ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसकी कीमत देश की जनता गैस संकट से चुका रही है।

किशोर की संदिग्ध मौत, सोडा वाटर पीने के बाद बिगड़ी तबियत

भोपाल। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित जिंसी पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले 17 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शार्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो सकेगा कि मौत कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुई है अथवा अन्य कोई वजह है। पुलिस के मुताबिक जिंसी पुलिस चौकी के पीछे जहांगीराबाद निवासी अब्दुल रहमान (17) निजी काम करता था। परिजनों ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी थी, और सिर-दर्द की समस्या रहती थी। सोमवार रात उसे उल्टी होने पर तबीयत बिगड़ने लगी परिजनो ने जब उससे पूछा तब उसने बताया कि उसने सोडा वाटर पीया था। मंगलवार सुबह परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां इलाज के दौरान बुधवार रात उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालो को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिर्पोट आने पर ही मौत के कारणो का खुलासा हो सकेगा जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की दिशा तय की जायेगी।

नई शिक्षा व्यवस्था से विद्यार्थियों को मिलेगा बहु-विषयक ज्ञान- एसीएस राजन

'विकसित भारत, 2047 को लेकर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ

भोपाल ■ निसं

शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल द्वारा 'विकसित भारत ञ्च 2047: संस्कृति, ज्ञान तथा सततता पर अन्तर्विषयी दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसका शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने शुभारंभ किया। साथ ही महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर तैयार की गई स्मारिका एवं मोनोग्राफ का लोकार्पण भी किया।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा व्यवस्था में बहुविषयक अध्ययन पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बहु-विषयक ज्ञान प्रदान करना है। एसीएस राजन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के संतुलित और समग्र विकास के लिए मानव मूल्यों, संस्कृति, विरासत और पर्यावरण के संरक्षण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ-साथ कला और सामाजिक विषयों से भी जुड़ाव उतना ही आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

शोध-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे: संगोष्ठी के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र-छात्राएं अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही विकसित भारत 2047 की संकल्पना के संदर्भ में संस्कृति, ज्ञान परंपरा और सतत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श भी किया जा रहा है।

संगोष्ठी में आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त, उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, नई दिल्ली आर.आर. रश्मि, पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास, साहित्यकार उदयन वाजपेई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ऌद्ब) के डॉ. मनोज कुमार कुर्मी, जनजातीय संग्रहालय, भोपाल के निदेशक डॉ. धर्मेंद्र पारे तथा दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉ. मुकेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में विद्वान एवं महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं।

श्री राजन ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन

अपर मुख्य सचिव श्री राजन ने दो दिसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में महाविद्यालय परिसर में विभिन्न संकायों द्वारा लगाई गए एक विशेष अन्तर्विषयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद कर प्रदर्शनी के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इसके साथ ही प्राचीन सिक्कों का संग्रह, सम्राट विक्रमादित्य के सिक्के, उज्जैन के महाकाल मंदिर से संबंधित सिक्के तथा अन्य कालखंडों के दुर्लभ सिक्कों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास द्वारा संग्रहित प्राचीन औजार, पंचांग, डाक टिकट तथा अन्य पुरावस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया। महाविद्यालय द्वारा स्वराज संस्थान, भोपाल के सहयोग से 'वंदे मातरम्' की ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की उत्पत्ति, स्वतंत्रता संग्राम में उसकी प्रेरक भूमिका तथा भारतीय राष्ट्रीय चेतना में उसके महत्व को भी प्रदर्शित किया गया।

पुलिस के पहरे में बंटेगी रसोई गैस, सुरक्षा को लेकर कलेक्टरों को निर्देश

प्रदेश में हॉस्टल और अस्पतालों को कमर्शियल गैस सिलंडर की छूट

भोपाल ■ निसं

युद्ध के चलते उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने एलपीजी आपूर्ति की निगरानी शुरू कर दी है। दो दिन पहले सरकार ने गैस के वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी है। जिसके चलते शैक्षणिक और चिकित्सीय संस्थाओं में भी गैस का संकट गहरा गया था। कुछ संस्थाओं में भोजन नहीं बनने जैसी शिकायतें भी सरकार तक पहुंची। इस बीच राज्य सरकार ने गुरुवार को वाणिज्यिक एलपीजी गैस उपयोग के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सकीय संस्थान को छूट दे दी है।

मप्र के आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने बताया है कि एलपीजी की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए जिलों को निर्देश दिये गये हैं। जिलों द्वारा इस क्षेत्र में लगातार कार्यवाही की जा रही है। एलपीजी के वैकल्पिक साधनों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही ऐसी गतिविधियों, जिनमें एलपीजी का अधिक उपयोग होता है, उन्हें नियंत्रित करने पर भी जोर दिया गया है। शर्मा ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस उपयोग के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सकीय संस्थान को छूट दी गई है, जो जारी रहेगी, जिससे शैक्षणिक गतिविधि एवं चिकित्सकीय व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रह सके। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी की सुचारू रूप से वितरण हो रहा है।

राजधानी में होटल, मॉल, उद्योगों को गैस सप्लाई पर रोक: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश में सभी ऑयल कंपनियों ने एलपीजी गैस की आपूर्ति सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को की जा रही है। इस बीच ऑयल कंपनियों ने शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थाओं को भी एलपीजी आपूर्ति की व्यवस्था शुरू की है।

'02 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा' के लिए रवाना होगी आईआरसीटीसी की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन

भोपाल ■ निसं

मध्यप्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन दिनांक 10.06.2026 को इंदौर से '02 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण दर्शन यात्रा' के लिए रवाना होगी।

यह विशेष पर्यटक ट्रेन मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल एवं नागपुर स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जहां से यात्री इस ट्रेन में सवार हो सकेंगे।

10 रात/11 दिन की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों को मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), रामेश्वरम, कन्याकुमारी एवं तिरुपति बालाजी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।

इस यात्रा के लिए प्रति यात्री पैकेज दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं–

- ●20,250/- प्रति व्यक्ति (SL - इकोनॉमी श्रेणी)
- ●33,500/- प्रति व्यक्ति (3AC - स्टैंडर्ड श्रेणी)
- ●44,100/- प्रति व्यक्ति (2AC - कंफर्ट श्रेणी)

आईआरसीटीसी द्वारा इस विशेष पर्यटक ट्रेन के पैकेज में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शामिल की गई हैं, जिनमें आरामदायक रेल यात्रा, ऑन-बोर्ड एवं ऑफ-बोर्ड भोजन, गुणवत्तापूर्ण बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण, यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, टूर एस्कॉर्ट, यात्रा बीमा तथा ऑन-बोर्ड सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग सेवाएं शामिल हैं।

इच्छुक पर्यटक इस यात्रा की बुकिंग आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से करा सकते हैं। यात्रा से संबंधित अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए पर्यटक आईआरसीटीसी के भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर रेलवे स्टेशन स्थित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

भोपाल मंडल होकर गोरखपुर से पुणे एवं मुम्बई के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन

भोपाल ■ निसं

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु समर सीजन पर यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भोपाल मंडल होकर गोरखपुर-पुणे एवं पुणे-गोरखपुर-पुणे एवं सीएसएमटी-गोरखपुर-सीएसएमटी के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह स्पेशल ट्रेनें इस प्रकार है:-

■ ट्रेन संख्या 01415/01416 पुणे-गोरखपुर-पुणे प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन (30-30 ट्रिप)

ट्रेन संख्या 01415 पुणे-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 01 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन पुणे स्टेशन से सुबह 06:50 बजे प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन सायं 16:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मंडल के इटारसी, रानी कमलापति एवं बीना स्टेशनों से गुजरेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 01416 गोरखपुर-पुणे स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 02 अप्रैल से 01 मई 2026 तक प्रतिदिन सायं 17:30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 03:15 बजे पुणे पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मंडल के बीना, रानी कमलापति एवं इटारसी स्टेशनों से गुजरेगी।

कोच कम्पोजीशन:- इस गाड़ी में 01 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 05 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 06 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 18 कोच रहेंगे।

ट्रेन के हाल्ट:- रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर जंक्शन (अहमदनगर), कोपरगाँव, मनमाड, भुसावल, खण्डवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, कानपूर सेन्ट्रल, लखनऊ, गोंडा एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

■ ट्रेन संख्या 01079/01080 सीएसएमटी-गोरखपुर-सीएसएमटी प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन (30-30 ट्रिप)

ट्रेन संख्या 01079 सीएसएमटी-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 01 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सीएसएमटी स्टेशन से रात 22:30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मंडल के इटारसी, भोपाल एवं बीना स्टेशनों से गुजरेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 01080 गोरखपुर-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 03 अप्रैल से 02 मई 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 14:30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन मध्यरात्रि 00:40 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन मंडल के बीना, भोपाल एवं इटारसी स्टेशनों से गुजरेगी।

कोच कम्पोजीशन:- इस गाड़ी में 01 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 06 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 09 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 22 कोच रहेंगे।

नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में खुलासा

मप्र की औसत रैंकिंग नौवें से दसवें स्थान पर गिरी

भोपाल ■ निसं

नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण मप्र की रैंकिंग में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार मप्र की औसत रैंकिंग एक अंक गिरकर नौवें से 10वें क्रम पर आ गई है। राज्य का स्कोर 37.8 है। सबसे अच्छी स्थिति में 73.1 अंक के साथ ओडिशा है। इसके बाद क्रमशः गोवा और झारखंड हैं, जबकि सबसे खराब स्थिति में पंजाब 18वें पायदान पर है। हालांकि, नीति आयोग ने मध्य प्रदेश को अभी भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में बरकरार रखा है। दूसरी ओर खर्च की गुणवत्ता के मामले में मप्र अच्छी स्थिति में है। इसमें प्रदेश सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों में 60.8 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार पैसा पूंजीगत क्षेत्र और विकासात्मक गतिविधियों में खर्च कर रही है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पर पांच लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि राज्य का वर्ष 2026-27 का कुल बजट 4.38 लाख करोड़ रुपये है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ऋण स्थिरता (डेब्ट सस्टेनेबिलिटी) ने मप्र की वित्तीय सेहत बिगाड़ दी है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (एफएचआई) रिपोर्ट के अनुसार यह स्कोर 2.2 है जो देश के 18 बड़े राज्यों में सबसे कम है। इसका मतलब यह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और ब्याज भुगतान के बीच अंतर बहुत कम है। इससे कर्ज को संभालना मुश्किल हो सकता है। ऋण स्थिरता सूचकांक में अंक जितने अच्छे रहते हैं, उसमें यह माना जाता है कि कर्ज चुकाना राज्य के लिए उतना ही आसान है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाने वाला राज्यों का एक आर्थिक प्रगति पत्रक है। यह पांच पैमानों पर मापता है कि कौन सा राज्य अपनी कमाई, खर्च और कर्ज का प्रबंधन कितने बेहतर तरीके से कर रहा है। वहीं ऋण स्थिरता किसी राज्य द्वारा लिए गए कर्ज को बिना किसी आर्थिक संकट के आसानी से चुकाने की क्षमता। मध्य प्रदेश इसी मामले में पिछड़ गया है। जबकि पूंजीगत व्यय सरकार का वह पैसा जो लंबे समय तक काम आने वाली संपक्षियों जैसे नई सडक़ें अस्पताल या स्कूल को बनाने में खर्च होता है। मध्य प्रदेश इस अच्छे खर्च में देश में तीसरे नंबर पर है।

विकासात्मक कार्यों पर अधिक खर्च: रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है की विकासात्मक कार्यों पर खर्च तो अधिक हो रहा है, लेकिन प्रतिबद्ध (कमिटेड) खर्च जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान आदि राजस्व आय की तुलना में अधिक होने के कारण वित्तीय स्थिति को अच्छा नहीं माना जा रहा है। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब नीति आयोग ने एफएचआई जारी किया है। साल 2025 में जारी वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश 42 अंकों के साथ नौवें पायदान पर था, इस बार रैंकिंग में एक अंक गिरकर दसवें नंबर पर आ गया है।

पुलिस कमिशनर से लोगो ने की नशेड़ियों के उत्पात मचाने की शिकायत

भोपाल ■ निसं

नशे की हालत में बदमाश शाम से ही हंगामा करना शुरू कर देते, वहीं गश्त के लिए पुलिसकर्मी भी कम ही आते हैं, जिसकी वजह से आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद रहते हैं। ऐसी शिकायतें भीम नगर के रहवासियो ने पुलिस आयुक्त संजय कुमार से कीं।

कमिशनर यहॉ लोगो से जनसंवाद के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि शहर में अपराध की नब्ज समझने व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आयुक्त पदभार संभालने के बाद से ही पूरे शहर की कॉलोनियों व बस्तियों में भ्रमण कर लोगों की बात सुन रहे हैं। इस दौरान वे शिकायतें मिलने पर कार्रवाई रहे हैं, तो वहीं लोगों को साइबर क्राइम से सतर्क रहने तथा यातायात नियमों का पालन करने को कह रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त जनसंवाद करने के लिए भीम नगर बस्ती में पहुंचे। यहां पर उन्होंने साइबर ठगी से बचाव, यातायात नियमों के पालन एवं मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में जनसहयोग का आह्वान किया तथा नागरिकों को हेलमेट व सीट बेल्ट के नियमित उपयोग की शपथ दिलाई।

अनमोल वचन

वृक्ष अपने सिर पर गरमी सहता है पर अपनी छाया में दूसरों का ताप दूर करता है।
तुलसीदास

सज्जन पुरुष बादलों के समान देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं।
कालिदास

सम्पादकीय

गैस संकट: सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत?

देश के कई हिस्सों में रसोई गैस को लेकर जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, उसने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के पास ना तो रसोई गैस है ना केरोसिन तेल है और ना ही लकड़ी उपलब्ध हो रही है। कई स्थानों पर तो बिजली सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में घर में खाना बनाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। एक ओर सरकार दावा कर रही है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। देश के सैकड़ो स्थान से इस बात के वीडियो और फोटो समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में प्रदर्शित हो रहे हैं। कई स्थानों पर डीलर खुले तौर पर कह रहे हैं, उनके पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है। पिछले कई दिनों से गैस की बुकिंग और सप्लाई बंद है। यह विरोधाभास केवल प्रशासनिक, नीतिगत और व्यवस्था की समस्या नहीं है वरन उन करोड़ों लोगों की समस्या है जिनके घर पर ना तो चाय बन पा रही है ना खाना बन पा रहा है। जो सरकार के दावों की हकीकत को उजागर कर रहा है। भारत में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों-इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा निजी गैस कंपनियां भी गैस सप्लाई करती हैं लेकिन सभी कंपनियों की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। सरकार का तर्क है, इन कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार है। वितरण प्रणाली सामान्य रूप से चल रही है, पर वास्तविकता में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे है। 1800 से 2000 रुपए में एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर कालाबाजारी से मिल रहा है। वही कमर्शियल गैस सिलेंडर 4000 रुपये तक में बिक रहा है। सरकार इसे वितरण तंत्र की गंभीर खामी बताकर पल्ला झाड़ रही है। जमीनी स्तर पर डीलरों का कहना है, उन्हें कंपनियों से समय पर पर्याप्त संख्या में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पोर्टल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। गैस डीलर भी जिस माध्यम से बुकिंग करते हैं उसका भी पोर्टल बार-बार या तो धीमा हो जाता है या बंद हो जाता है। जिसके कारण वह उपभोक्ताओं की मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को कई दिनों तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। जिसके कारण करोड़ों घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। इससे सवाल उठता है, यदि उत्पादन और भंडारण पर्याप्त है, तो फिर गैस की आपूर्ति में बाधा क्यों है? इस समस्या से आम आदमी से लेकर होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों और शादी ब्याह के आयोजनों में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। गैस के कारण मात्र असुविधा नहीं वरन गैस लूटने तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। रसोई गैस आम परिवारों की बुनियादी आवश्यकता है। इसका कोई विकल्प भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों के करोड़ों परिवार एलपीजी गैस पर निर्भर हैं। ऐसे में गैस की आपूर्ति बाधित होने पर इसका सीधा असर करोड़ों लोगों के जीवनयापन और छोटे व्यवसायों पर पड़ा है। सरकार केवल बयान देने तक सीमित न रहे। सरकार और कार्यपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह गैस की आपूर्ति प्रणाली की वास्तविक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास करे। गैस की आपूर्ति को लेकर जमाखोरी, परिवहन या वितरण में गड़बड़ी है, तो उस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शी एवं जवाबदेही के लिए संवाद जरूरी है, सार्वजनिक क्षेत्र में और मंदिर इत्यादि में जहां लंगर इत्यादि गरीबों के लिए चलाए जाते हैं वहां पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। यदि सरकार का दावा सही है, गैस की कमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनता को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई है? इस प्रश्न का स्पष्ट और ईमानदार उत्तर देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। गैस संकट का वास्तविक समाधान तभी हो सकता है, जब सभी पक्ष ईमानदारी के साथ वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपस में सहयोग करें। गैस, पेट्रोल, डीजल अब सभी लोगों से नियमित रूप से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और ना ही इसे झुठलाया जा सकता है। सभी पक्ष जितनी जल्दी हकीकत को समझ लेंगे, समस्या का समाधान उतनी ही जल्दी निकाल पाएंगे।

चिंतन-मनन

इच्छा का लक्ष्य है खुशी

बुरी आदत को छोड़ने की असमर्थता तुम्हें तकलीफ देती है। जब तुम बहुत पीड़ित होते हो, वह व्यथा तुम्हें उस आदत से छुटकारा दिलाती है। जब तुम अपनी कमियों से व्यथा महसूस करते हो, तब तुम साधक हो। पीड़ा तुम्हें आसक्ति से दूर करती है। यदि अपने दुर्गुणों को हटा नहीं सकते, तो उन्हें विस्तृत कर दो। चिन्ता, अभिमान, प्रोध, कामना, दुख सबको एक और बड़ा आयाम दे दो, एक दूसरी दिशा। छोटे-छोटे विषयों पर नाराज होने का क्या तुक है? नाराज होना है तो अनन्तता के प्रति, ब्रह्म के प्रति हो। यदि तुम अपने अहंकार को नहीं खत्म कर सकते तो अहंकार करो कि ईश्वर तुम्हारे हैं। यदि आसक्ति तुम पर छाई है, तो सत्य के प्रति आसक्त हो जाओ। यदि ईर्ष्या तुम्हें सताती है, तो सेवा के लिए ईर्ष्या करो। द्वेष के प्रति द्वेष रखो; गुरु से राग करो। दिव्यता के प्रति मदहोश हो जाओ।

इन्द्रिय सुखों की इच्छाएं विद्युत की तरह हैं; जैसे-जैसे वे विषय विस्तुओं की ओर बढ़ती है, निष्प्रभावी हो जाती हैं। अपनी कुशलता से यदि तुम इच्छाओं को अपने भीतर मोड़ सको- अपने अस्तित्व के केन्द्र की ओर- तो तुम्हें मिलेगा एक और आयाम- चिरन्तन सुख, रोमांच, परमानन्द और शात प्रेम। वासना, लोभ और ईर्ष्या इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि ये केवल ऊर्जा हैं और तुम ही इनके स्रेत हो- वह विशुद्ध ऊर्जा। निष्ठा और भक्ति तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखती हैं, तुम्हें उन्नत करती हैं।

जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम स्वयं ही सुख की विद्युत धारा हो, तुम्हारी लालसाएं घटने लगती हैं और प्रशांति आती है। मृत्यु निश्चित है - यह याद रखने से तुम वर्तमान क्षण में सजीव रहते हो, राग और द्वेष से मुक्त। इच्छा खुशी को खत्म करती है, लेकिन सभी इच्छाओं का लक्ष्य है खुशी। जब भी जीवन से खुशी गायब होने लगे, भीतर गहराई में झांककर देखो- तुम पाओगे यह इच्छा के कारण हो रहा है। लेकिन हमारी इच्छा ही केवल खुशी है। कोई जीव आज तक पैदा नहीं हुआ जिसे दु:ख की चाह हो- न ऐसा पहले कभी हुआ है, न भविष्य में होगा। जब तुम्हारा छोटा मन इधर-उधर, जब जगह भागते-भागते थक जाता है, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, मेरी इच्छाओं ने मेरी खुशी छीन ली है।

संसद में हंगामा और वास्तविक मुद्दों से भटकती राजनीति

कांतिलाल मांडोत

इसलिए जब संसद में गंभीर विषयों पर विचार के बजाय लगातार हंगामा और टकराव देखने को मिलता है तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में निराशा पैदा होती है। हाल के दिनों में संसद के दोनों सदनों में जो स्थिति देखने को मिली उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं या फिर संसद को केवल राजनीतिक रणनीति का मंच बना दिया गया है।

लोकतंत्र में संसद केवल बहस का मंच नहीं होती बल्कि वह देश की सामूहिक बुद्धि और जिम्मेदारी का प्रतीक भी होती है। यहा लिए गए निर्णय देश की दिशा तय करते हैं और यहां होने वाली चर्चाएं करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब संसद में गंभीर विषयों पर विचार के बजाय लगातार हंगामा और टकराव देखने को मिलता है तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में निराशा पैदा होती है। हाल के दिनों में संसद के दोनों सदनों में जो स्थिति देखने को मिली उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं या फिर संसद को केवल राजनीतिक रणनीति का मंच बना दिया गया है।

सोमवार को संसद के सत्र में अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि इस अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के असर पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए। यह मांग अपने आप में गलत नहीं कही जा सकती क्योंकि मध्य पूर्व की घटनाओं का असर भारत सहित दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में इस विषय पर चर्चा की मांग को पूरी तरह असंगत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इसे लेकर संसद की कार्यवाही बाधित की उसने इस मांग की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए।

लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी बन गई कि महज कुछ ही मिनटों में सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में जब विदेश मंत्री स्सुभरमन्यम जयशंकर ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखने के लिए बयान देना शुरू किया तो भी विपक्ष ने विरोध जारी रखा। विपक्ष का कहना था कि मंत्री के बयान से पहले इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए ताकि वे सरकार से सवाल पूछ सकें। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि पहले मंत्री का वक्तव्य सुना जाए और उसके बाद चर्चा हो सकती है। इस टकराव के बीच सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अंतत: पूरे दिन कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। विपक्ष ने पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। संसदीय परंपरा के अनुसार जब ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसे सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उस पर चर्चा हो सके। लेकिन जब सभापति जगदम्बिका पाल ने विपक्ष से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा तो विपक्ष ने ऐसा करने से परहेज किया और हंगामा जारी रखा। इससे यह संदेश गया कि विपक्ष स्वयं अपने प्रस्ताव को लेकर स्पष्ट नहीं है और उसकी प्राथमिकता वास्तविक बहस से अधिक राजनीतिक दबाव बनाना है।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने भी इसी बात को उठाते हुए कहा कि विपक्ष खुद ही कंफ्यूज है कि वह करना क्या चाहता है। उनका तर्क था कि पहले स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया गया और फिर दूसरा मुद्दा उठाकर हंगामा किया जा रहा है। दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मध्य पूर्व में तेजी से बदल रहे हालात का भारत पर असर पड़ रहा है इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। उनके अनुसार तेल की कीमतों में वृद्धि और खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा जैसे मुद्दे गंभीर हैं और सरकार को इस पर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

दरअसल यह सच है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ता है और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण चिंता होती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अमेरिका और ईरान जैसे शक्तिशाली देशों के बीच चल रहे युद्ध को भारत अपने स्तर पर रोक नहीं सकता। भारत एक जिम्मेदार कूटनीतिक भूमिका जरूर निभा सकता है और शांति की अपील कर सकता है लेकिन किसी अंतरराष्ट्रीय युद्ध को रोक देना उसके हाथ में नहीं होता। ऐसे में इस विषय को लेकर संसद में लगातार हंगामा करना कहीं न कहीं राजनीतिक रणनीति अधिक और वास्तविक समाधान की कोशिश कम दिखाई देता है।

संसद का समय अत्यंत मूल्यवान होता है। सभापति ने यह भी याद दिलाया कि संसद के हर मिनट पर लाखों रुपये खर्च होते हैं और यह पैसा अंतत: जनता का ही होता है। जब संसद का समय हंगामे में नष्ट होता है तो उसका नुकसान केवल सरकार या विपक्ष को नहीं बल्कि पूरे देश को होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनकर भेजती है ताकि वे उनकी समस्याओं को उठाएं और समाधान के लिए ठोस चर्चा करें। लेकिन जब बहस के बजाय शोर और टकराव हावी हो जाता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है।

आज देश के सामने अनेक गंभीर मुद्दे हैं जिन पर संसद में सार्थक चर्चा की आवश्यकता है। बेरोजगारी आर्थिक असमानता महंगाई कृषि संकट और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी समस्याएं सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि विपक्ष इन मुद्दों को मजबूती से उठाए तो उसे जनता का व्यापक समर्थन मिल सकता है। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वह विपक्ष को चर्चा का पर्याप्त अवसर दे और लोकतांत्रिक संवाद की भावना को मजबूत करे।

लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर राष्ट्रीय हित में काम करें। असहमति लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है लेकिन असहमति का अर्थ केवल विरोध करना नहीं बल्कि रचनात्मक बहस करना भी होता है। यदि संसद में हर मुद्दा केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और हंगामे का कारण बन जाएगा तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर संसद की गरिमा को प्राथमिकता दें। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा जरूर होनी चाहिए लेकिन वह चर्चा तथ्य और तर्क पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में। जब संसद में गंभीर बहस होगी तभी जनता का विश्वास मजबूत होगा और लोकतंत्र की वास्तविक भावना भी कायम रहेगी।

(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार स्तम्भकार)

अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति एवं लोकतांत्रिक मूल्य

ललित गर्ग

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक गंभीर संसदीय कदम माना जाता है। यह केवल राजनीतिक विरोध का साधन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे ठोस तर्क, गंभीर आरोप और व्यापक समर्थन होना अपेक्षित होता है। किंतु जिस प्रकार विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाया और बाद में उसकी गंभीरता का अभाव दिखाया, उसने इस पूरी प्रक्रिया को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब यह प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हुआ तो विपक्ष ने मतदान की मांग तक नहीं की। यदि विपक्ष को अपने प्रस्ताव पर पूरा विश्वास होता और उसे लगता कि वह सदन का समर्थन प्राप्त कर सकता है।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसद है, जहां न केवल कानून बनते हैं बल्कि राष्ट्र की दिशा और दशा पर गंभीर विमर्श भी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी भूमिका को लोकतांत्रिक तरीके से जिम्मेदारी, संयम और मर्यादा के साथ निभाएं, यह नितांत अपेक्षित है। किंतु हाल के दिनों में जिस तरह से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में आया, उसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या विपक्ष वास्तव में संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर है या वह केवल स्वार्थ की राजनीतिक करने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक गंभीर संसदीय कदम माना जाता है। यह केवल राजनीतिक विरोध का साधन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे ठोस तर्क, गंभीर आरोप और व्यापक समर्थन होना अपेक्षित होता है। किंतु जिस प्रकार विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाया और बाद में उसकी गंभीरता का अभाव दिखाया, उसने इस पूरी प्रक्रिया को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब यह प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हुआ तो विपक्ष ने मतदान की मांग तक नहीं की। यदि विपक्ष को अपने प्रस्ताव पर पूरा विश्वास होता और उसे लगता कि वह सदन का समर्थन प्राप्त कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से मत विभाजन की मांग करता। लेकिन ऐसा न होना इस तथ्य को ही पुष्ट करता है कि विपक्ष स्वयं भी जानता था कि यह प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक स्थिति तब देखने को मिली जब प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर आया तो विपक्ष ने स्वयं उस पर चर्चा करने के बजाय पश्चिम एशिया के संकट पर बहस की मांग शुरू कर दी। यह विषय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, किंतु यदि विपक्ष ने स्वयं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो उसे पहले उसी पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा से पीछे नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही को नियमों और प्राथमिकताओं के अनुसार चलाना आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस अपने ही प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं थी। इस अवसर पर ही नहीं, अनेक अवसरों पर उसने गैर-जिम्मेदारी एवं बचकानेपन का अहसास कराया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। किंतु जब विपक्ष केवल राजनीतिक आरोपों और शोर-शराबे तक सीमित रह जाए तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ने लगता है। यहां सत्ता-पक्ष के लिये भी यह गौर करने की बात है कि आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बातों को अनसुना किया जाता है? पक्ष एवं विपक्ष दोनों को ही विश्वास, समन्वय एवं सौहार्द बनाये रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का व्यवहार भी कई बार संसदीय मर्यादाओं के संदर्भ में चर्चा का विषय बना है। यह सच है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें सरकार की आलोचना करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि संसदीय नियमों और परंपराओं को दरकिनार कर दिया जाए। संसद की कार्यवाही स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन चलती है और इन नियमों का पालन करना हर सांसद की जिम्मेदारी है। बीते कुछ समय से राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर यह आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के मामले में प्रधानमंत्री ने समर्पण कर दिया है। इस तरह के आरोपों को उन्होंने कई मंचों पर दोहराया है, किंतु इन दावों के समर्थन में ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार उन्होंने चुनाव आयोग पर भी यह आरोप लगाया कि वह मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले होते हैं और यदि इन्हें प्रमाणों के बिना बार-बार दोहराया जाए तो यह लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए भी उचित नहीं माना जा सकता। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में विस्तार से यह बताया कि लोकसभा अध्यक्ष पर बोलने का अवसर न देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने स्वयं कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संसद के विभिन्न सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही है और कई बार महत्वपूर्ण बहसों के दौरान वे विदेश यात्राओं पर रहे। इन तथ्यों को सामने रखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि संसद में सक्रिय भागीदारी ही कम होगी तो संसदीय विमर्श को प्रभावी कैसे बनाया जा सकेगा। जहां तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रश्न है, उनका कार्यकाल कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने सदन की कार्यवाही को संतुलित, संयमित और नियमबद्ध ढंग से संचालित करने का प्रयास किया है। उनके नेतृत्व में संसद की कार्यवाही को अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए। उन्होंने सांसदों को समयबद्ध तरीके से बोलने का अवसर देने, युवा सांसदों को अधिक सक्रिय करने और संसदीय समितियों की भूमिका को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया।

एलपीजी की जगह चूल्हा एक सस्ता विकल्प

संजय गोस्वामी

12 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच फारस की खाड़ी में गंभीर तनाव और संघर्ष जारी है, जो 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान द्वारा समर्थित गुटों ने अमेरिकी और खाड़ी देशों के तेल टैंकरों पर हमले किए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट खड़ा हो गया है। युद्ध की स्थिति का सीधा असर होटल मालिकों पर पड़ने वाला है। संभावना है कि कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक खत्म होने पर होटल को जल्द ही बंद करना पड़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कमी पूरे देश में एलपीजी का संकट है एलपीजी सप्लाई में रुकावट का असर अब इंडिया इंक पर भी पड़ रहा है, कुछ कंपनियों ने कुकिंग गैस की कमी के कारण कैफेटेरिया और फूड सर्विस पर असर पड़ने की वजह से ऑपरेशनल दिक्कतों की रिपोर्ट दी है। साथ ही, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में रुकावट की खबरें आई हैं, रेस्टोरेंट और खाने की जगहों को सिलेंडर खरीदने में मुश्किल हो रही है और कुछ मामलों में मेन्यू कम कर दिए गए हैं या ऑपरेशन कम कर दिए गए हैं। कई राज्यों में पुलिस ने भी एलपीजी सप्लाई को लेकर अफवाहों के बीच मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, और गलत जानकारी, जमाखोरी और सिलेंडर की चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि, सरकार का कहना है कि पूरे देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है और सप्लाई को स्थिर करने के लिए रिफाइनरी का आउटपुट लगभग 10% बढ़ा दिया गया है। एलपीजी सप्लाई, सरकार की प्रतिक्रिया और भारतीय शहरों की स्थिति पर लेटेस्ट अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग को फॉलो करें। एलपीजी सप्लाई की कमी से पूरे भारत में होटल, रेस्टोरेंट पर असर है युद्ध के इस दौर में, गोबर से बनी बायोगैस या गोबर के उपले एलपीजी का एक आत्मनिर्भर और किफायती विकल्प प्रदान करते हैं चूल्हा एक ऐसा उपकरण है जो स्थानीय ताप या खाना पकाने के लिए उपकरण के अंदर या ऊपर ऊष्मा उत्पन्न करता है। चूल्हे कई प्रकार के ईंधनों से चल सकते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, बिजली, गैसोलीन, लकड़ी और कोयला। चूल्हे के निर्माण के लिए सबसे आम सामग्री कच्चा लोहा, इस्पात और पत्थर हैं। चूल्हे और गोबर के उपले भारतीय ग्रामीण जीवन, संस्कृति और परंपरा के अभिन्न अंग हैं। मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले न केवल सस्ते और आसानी से उपलब्ध ईंधन हैं, बल्कि आत्मीयता और पवित्रता का भाव भी रखते हैं। आत्मनिर्भरता, सादगी और पर्यावरण मित्रता के प्रतीक के रूप में ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव: पुराने धुंआ उत्सर्जित करने वाले चूल्हे महिलाओं और बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए लोग अब धुआं रहित चूल्हों की ओर बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की कहानी: कई परिवार बायोगैस के माध्यम से आत्मनिर्भर हो गए हैं, वे गोबर से 8-10 घंटे तक चूल्हे को जलाते हैं। चूल्हा और गोइठा का संबंध केवल भोजन पकाने से नहीं, बल्कि एक जीवनशैली से है जो हमें प्रकृति के करीब रखती है। यह हमारे पूर्वजों की विरासत और सादगी का प्रतीक है, जिसे आज भी ग्रामीण भारत में संजोकर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में आज भी लोग पुराने और पारंपरिक ईंधनों का उपयोग न सिर्फ अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, बल्कि परंपराओं के अनुसार धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं. होली के पर्व से पहले गांवों में घरों में पाले गए मवेशियों के गोबर से गोईठा बनाया जाता है.मान्यता है कि गोबर शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है, यही कारण है कि होली के दिनों में गोईठा की मांग बढ़ जाती है. कई लोग इसे बनाकर बेचते हैं, वहीं जिनके पास गोईठा उपलब्ध नहीं होता, वे गांवों से इसे लाकर होलिका दहन करते हैं. यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और सदियों पुरानी जीवनशैली की गहराई को भी दर्शाती है. चूल्हा और गोइठा: ग्रामीण जीवन के प्रतीक पारंपरिक संस्कृति: गाँव में मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना - विशेषकर रोटी, दाल और बाटी - स्वाद और सौंधी महक के लिए जाना जाता है।

खास बात

चैनलों की टीआरपी पर रोक

पहली बार भारत सरकार ने टेलीविजन मीडिया की गैर जिम्मेदारी को लेकर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया है। ईरान- इजरायल युद्ध की कवरेज मे जिस तरह से चेनेलों द्वारा कार्यक्रम के दौरान युद्ध के सायरन बजाए जा रहे थे। उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। चैनल युद्ध को भड़काने वाली बात करते थे। तबीयत से झूठ दिखा रहे थे। पहली बार केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने चैनलों को जिम्मेदार बनाने के लिए टीआरपी रोकने के आदेश दिए हैं। जिन चैनलों को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ा किया था। वही चैनल अब सरकार और भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कार्यवाही तो होनी ही थी, जय श्री राम

नेता नहीं, तो एयरोस्पेस कारोबारी बनता

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर थे। उन्होंने त्रिवेंद्रम में कहा, यदि वह नेता नहीं बने होते, तो निश्चित रूप से एयरोस्पेस के कारोबारी बनते। उनका हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनने का सपना था। उनके पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी दोनों पायलट थे। हवा में उड़ते थे। वह भी अपना करियर एयरोस्पेस में बनाना चाहते थे। जो सोचते हैं, जो हम युवावस्था में सोचते हैं, वह पूरा नहीं होता है। जो होता है, उसे हम सोच भी नहीं पाते हैं। यही उनके पिता राजीव गांधी के साथ हुआ था। इसी को कहते हैं, होई वही जो राम रचि राखा।

स्टेट बैंक की राजनीतिक दलों को सलाह

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है। वह मुफ्त उपहार और बैंक खाते से नगदी खैरात बांटने से बचें। स्टेट बैंक ने कहा, इससे देश का विकास रुक रहा है। जो काम सरकारों को करना होता है। वह काम अब बैंक और न्यायालयों के जिम्मे डाला जा रहा है। इसी को कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे बैंक खुद लाखों करोड़ रुपए बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बट्टे खाते में डाल रही हैं। उस पर बैंकों ने चुप्पी साध रखी है। केंद्र सरकार खुद कुछ नहीं कहती है। जिसका कोई लेना-देना नहीं होता उससे कहलावती है।

एलपीजी संकट से देशभर में हाहाकार

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद से जारी सैन्य संघर्ष का असर अब भारत के विभिन्न राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है। देशभर में रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और सिलेंडर की कालाबाजारी तथा जमाखोरी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बढ़ती एलपीजी किल्लत के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिखला दिया है कि अब यह आंदोलन का रुप लेने जा रहा है। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी सांकेतिक सिलेंडर, पोस्टर और अपने साथ मिट्टी के चूल्हे लेकर पहुंचे और सरकार से तत्काल आपूर्ति सामान्य करने की मांग की। यही स्थिति अब अन्य राज्यों के प्रमुख शहरों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार के दावों के विपरीत एलपीजी संकट देशभर में उभर कर सामने आया है।

राशिफल

शुभ संवत 2082, शाके 1947, सौम्य गोष्ठ, चैत्र कृष्ण पक्ष, शिशिर ऋतु, गुरु उदय पूर्वे, शुक्रोद्रय पश्चिमे तिथि, एकादशी, शनिवार, उत्तराषाढ़ नक्षत्रे, वल योगे, वव करणे, मकर की चंद्रमा, मीने रवि 50/30 सर्वार्थ सिद्ध योगे तथापि दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ उत्तम होगी।

आज जन्म लिए बालक का फल: आज जन्म लिया बालक योग्य, बुद्धिमान, चपल, चतुर, चंचल, स्वाभिमानी, उत्तम वृत्ति वाला, धनी-मानी, कुशल वक्ता-अधिवक्ता, शासक-प्रशासक, कर्मशील, उद्योगपति, किराना मर्चेन्ट, उत्तम कपड़ा व्यापारी होगा।

मेष राशि- कार्य व्यवसाय में विचलित होंगे, स्त्री शरीर कष्ट, मानसिक बेचैनी बनेगी।

वृष राशि- आकस्मिक बेचैनी, स्वभाव में खिन्नता, थकावट, असमंजस व अस्थिरता की स्थिति बनेगी।

मिथुन राशि- अकारण बेचैनी, शरीर कष्ट, चोट-चपेट व कष्टप्रद स्थिति बनेगी, धैर्य रखें।

कर्क राशि- धन लाभ, आशानुकूल सफलता से लाभ होगा, बिगड़े कार्य बनेंगे ध्यान दें।

सिंह राशि- मन में बेचैनी, धन लाभ, आशानुकूल सफलता से लाभ होगा, समय का ध्यान रखें।

कन्या राशि- अर्थलाभ कुटुम्ब की समस्यायें अवश्य ही सुलझेंगी, स्त्री कार्य से हर्ष होगा।

तुला राशि- विरोधी परेशान करेंगे, प्रतिष्ठा पर आंच आने का भय सावधान रहें, मानसिक तनाव।

वृश्चिक राशि- कार्यवृत्ति में सुधार, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, मित्रों के सहयोग से कार्य होंगे।

धनु राशि- अधिकारियों से तनाव व क्लेश, मान-प्रतिष्ठा बाल-बाल बचे, रुके कार्य बनेंगे।

मकर राशि- चिन्तायें कम होंगी, सफलता के साधन जुटायें, कार्य अवश्य ही होंगे।

कुंभ राशि- आर्थिक परेशानी हो सकती है, कार्यवृत्ति में सुधार होगा, समय का ध्यान रखें।

मीन राशि- इष्ट मित्र सुखवर्धक होंगे, आर्थिक योजना पूर्ण होगी, समय पर कार्य करें।

पीएल गौतमाचार्य

दैनिक पंचांग

14 मार्च 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

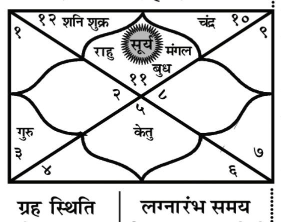

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	कुंभ में	मीन	06.16 बजे से
चंद्र	मकर में	मेष	07.47 बजे से
मंगल	कुंभ में	वृष	09.27 बजे से
बुध	कुंभ में	मिथुन	11.25 बजे से
गुरु	मिथुन में	कर्क	13.38 बजे से
शुक्र	मीन में	सिंह	15.54 बजे से
शनि	मीन में	कन्या	18.06 बजे से
राहु	कुंभ में	तुला	20.17 बजे से
केतु	सिंह में	वृश्चिक	22.32 ब.से
		धनु	00.48 बजे से
		मकर	02.53 बजे से
		कुंभ	04.39 बजे से

राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक

शनिवार 2026 वर्ष का 73 वा दिन **दिशाशूल** पूर्व **ऋतु** शिशिर। **विक्रम संवत्** 2082 **शक संवत्** 1947 **मास** चैत्र (दक्षिण भारत में फाल्गुन) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** दशमी 08.11 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** उत्तराषाढ़ा 04.49 बजे प्रात: को समाप्त। **योग** वरीयान 10.43 बजे को समाप्त। **करण** विष्टि 08.11 बजे तदनन्तर बव 20.49 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.5 घण्टे **रवि क्रान्ति** दक्षिण 02° 37' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872648 **जूलियन दिन** 2461113.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1447 **महीना** रमजान **तारीख** 24 **विशेष** कारादाइयन नौम्बू।

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
काल	05.55 से 07.23 बजे तक	लाभ	05.37 से 07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से 08.51 बजे तक	उद्वेग	07.10 से 08.42 बजे तक
रोग	08.51 से 10.19 बजे तक	शुभ	08.42 से 10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से 11.46 बजे तक	अमृत	10.14 से 11.47 बजे तक
चर	11.46 से 01.14 बजे तक	चर	11.47 से 01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से 02.42 बजे तक	रोग	01.19 से 02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से 04.10 बजे तक	काल	02.51 से 04.23 बजे तक
काल	04.10 से 05.37 बजे तक	लाभ	04.23 से 05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

संक्षिप्त समाचार

वाराणसी स्टेशन पर 3.54 करोड़ का सोना बरामद, दो गिरफ्तार

वाराणसी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से जीआरपी थाना के पुलिसकर्मियों ने दो किलो से अधिक सोना बरामद किया है। यह सोना अफ्रीका से बांग्लादेश होते हुए भारत पहुंचा था। इस मामले में जीआरपी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जीआरपी कैंट थाना के निरीक्षक राजोल नागर ने बताया कि महाराष्ट्र के सातार के निवासी बालासो व पूना निवासी तेजस को कैंट रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा है। यह दोनों शातिर किस्म के हैं और अक्सर इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों के पास से दो किलो से अधिक सोने के बिस्किट बरामद किये गए। बरामद सोने की कीमत करीब 3.54 करोड़ के करीब बताई जा रही है। इनके पास से बरामद सोना विशेष रूप से अफ्रीकी सोना है। पूछताछ में पता चला कि दोनों अफ्रीका से बांग्लादेश के रास्ते सोना लेकर भारत पहुंचे थे। जीआरपी पुलिस दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

नेपाल-भारत के बीच बिजली की खरीद और बिक्री की नई दरें लागू होंगी, बनी सहमति

काठमांडू। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से एक साल तक नेपाल को बिजली आयात करने और उसकी नई दर लागू करने पर सहमति बनी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार पोखरा में 12 और 13 मार्च को हुई एक बैठक में आगामी एक वर्ष के लिए बिजली खरीद दर निर्धारित की गई। बैठक में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक हितेंद्र देव शाक्य और भारत की ओर से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी के बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। वार्ता के दौरान भारत की ओर से बिजली उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए बिजली खरीद दर में 5.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। नेपाल की ओर से भारतीय बिजली बाजार के अध्ययन और उपलब्ध बाजार सूचकांकों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि वर्तमान बाजार दर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए दर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक शाक्य ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद पिछले वर्ष निर्धारित दर में केवल 1.5 प्रतिशत वृद्धि करने पर सहमति बनी, जो कि पिछले वर्ष की वृद्धि दर के समान है। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के लिए 132 केवी प्रसारण लाइन के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली की दर प्रति यूनिट 8.22 रुपये, 33 केवी स्तर पर प्रति यूनिट 8.91 रुपये तथा 11 केवी स्तर पर प्रति यूनिट 9.55 रुपये तय की गई है।

चीन की रेडक्रॉस सोसाइटी ईरान की आईआरसीएस को 2 लाख डॉलर की मदद देगी

बीजिंग/मॉस्को। ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के सैन्य टकराव के बीच चीन की रेडक्रॉस सोसाइटी ने ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी (आईआरसीएस) को आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर 2,00,000 अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। चीन ने ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हाल ही में हुए हमले में छात्रों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उधर, रूस की तरफ से राष्ट्रपति के आदेश पर अजरबैजान के रास्ते भेजी गई 13 टन मानवीय सहायता ईरान के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हमले में छात्रों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की रेडक्रॉस सोसाइटी ने ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर 200,000 अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु (एए) ने रूस के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से गुरुवार को बताया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर अजरबैजान के रास्ते ईरान को 13 टन मानवीय सहायता भेज गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रशिक्षु अधिकारियों से चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर दिया जोर

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को यहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) और रॉयल भूटान सेवा (आरबीएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। ज्ञानेश कुमार ने सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार के महत्व और लोकतांत्रिक एवं चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि आईआईआईडीईएम चुनाव आयोग का प्रमुख प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है जो न केवल भारतीय अधिकारियों बल्कि मित्र देशों के चुनावी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करता है।

एनएक्सटी कॉन्क्लेव नीति-निर्माण, नवाचार, वैश्विक सहयोग का बन रहा है अहम मंच : बिरला

नई दिल्ली ■ एजेंसी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2026 नीति-निर्माण, विचार-विमर्श, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। ऐसे मंच दुनिया भर के सांसदों, नीति-निर्माताओं को समकालीन वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर सार्थक चर्चा का अवसर प्रदान करते हैं।

बिरला ने यहां आयोजित एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2026 में भाग लेने आए 30 से अधिक देशों के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से शुक्रवार को संसद भवन में मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के जनप्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का संसद भवन में स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और वैश्विक संसदीय संवाद के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा की सराहना की, जिन्होंने एनएक्सटी 2026 कॉन्क्लेव पहल का नेतृत्व किया है। बिरला ने कहा कि यह पहल दुनिया भर के सांसदों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक विचार नेताओं को एक मंच पर लाकर शासन, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े विषयों पर सार्थक विमर्श को बढ़ावा दे रही है।

भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अक्सर 'लोकतंत्र की जननी' कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यह देश में संवाद, सहमति और सहभागी निर्णय-निर्माण की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। भारत की संसद 1.4 अरब नागरिकों की आकांक्षाओं और विविधता का प्रतिनिधित्व करती है, जहां नीतियां विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच बहस और संवाद के माध्यम से आकार लेती हैं। लोकतंत्र की यही शक्ति भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनाती है।

बिरला ने पिछले एक दशक में भारत द्वारा समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार और सुशासन के क्षेत्र में हासिल की गई प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना संभव हुआ है।

लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल संसद, उन्नत संसदीय अनुसंधान प्रणालियों और आधुनिक सूचना प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से संसद की कार्यप्रणाली को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। संसदीय कूटनीति के महत्व को रेखांकित करते हुए बिरला ने कहा कि भारतीय संसद ने हाल के वर्षों में विश्व की विभिन्न विधायिकाओं के साथ संवाद और सहयोग को मजबूत करने के लिए 60 से अधिक संसदीय मैत्री समूहों का गठन किया है। इन समूहों के माध्यम से विभिन्न देशों के सांसदों के बीच विचारों, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सांसदों के बीच ज्ञान और अनुभवों का व्यापक आदान-प्रदान आवश्यक है। इस तरह के संवाद वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए साझा समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं।

बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2026 के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से लोकतांत्रिक सहयोग, आपसी समझ और देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी। यह मंच वैश्विक लोकतांत्रिक समुदाय को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए साझा रणनीति बनाने का अवसर प्रदान करता है।उल्लेखनीय है कि एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2026 में विभिन्न देशों के सांसदों, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाया गया है। इस मंच पर शासन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े उभरते अवसरों और चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की जा रही है।

राज्यसभा में 'न्यायिक अतिरेक' का मुद्दा उठा

एनसीआरटी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाये सवाल

लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को समान रूप से जवाबदेह होना चाहिए

नई दिल्ली ■ एजेंसी

राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सदन में न्यायपालिका के बढ़ते हस्तक्षेप और 'न्यायिक अतिरेक' का मुद्दा उठाया। उन्होंने एनसीईआरटी विवाद और हालिया उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को समान रूप से जवाबदेह होना चाहिए।

सांसद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने न केवल एनसीईआरटी की किताबों से 'न्यायिक भ्रष्टाचार' से संबंधित अंश हटाने का निर्देश दिया बल्कि इस अध्याय को लिखने वाले शिक्षाविदों (प्रोफेसर माइकल डैनिनो और अन्य) को सार्वजनिक संस्थानों में किसी भी भूमिका से प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया। उन्होंने इसे 'न्यायिक तानाशाही' करार दिया।

चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि जहां राजनेताओं नौकरशाहों और आम नागरिकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की सघन जांच होती है। वहीं न्यायपालिका अपने ऊपर होने वाली चर्चा को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है। उन्होंने एक मौजूदा उच्च न्यायालय जज के खिलाफ लंबित महाभियोग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर केवल तबादला किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देने पर भी चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार आलोचना को पूरी तरह दबाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कानून मंत्री से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि देश में ऐसी स्थिति पैदा न हो जहां कोई भी संस्था खुद को कानून से ऊपर समझने लगे। उन्होंने स्पष्ट किया, 'शासन की तीनों शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कानून की नजर में समान तथा जांच के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। किसी भी एक शाखा की सर्वोच्चता राष्ट्र के लिए समस्या खड़ी कर सकती है।

बांग्लादेश में दो बसों में टक्कर, दूल्हा-दुल्हन समेत 14 की मौत

ढाका। बांग्लादेश में मोंगला-खुलना हाइवे पर बांग्लादेश नेवी की एक बस और एक यात्री मिनसी बस के बीच आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दूल्हा-दुल्हन और एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। यह हादसा गुरुवार शाम करीब 4 :00 बजे बेलाई पुल के पास हुआ। मिनी बस में शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के सदस्य सवार थे। विपरीत दिशा से आ रही नेवी की बस से मिनी बस की टक्कर के बाद चीख-पुकार मच गई।

आईबीएसए फंड जैसी वैश्विक साझेदारियां महिला सशक्तीकरण के नए आयाम स्थापित करेंगी: ठाकुर

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला स्थिति आयोग (सीएसडब्ल्यू) के 70वें सत्र में कहा कि भविष्य में इंडिया ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) फंड जैसी वैश्विक साझेदारियां समावेशी नीति निर्माण को सुदृढ़ और महिला सशक्तीकरण के नए आयाम स्थापित करेंगी।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में आयोजित सीएसडब्ल्यू का 70वां सत्र 'महिला नेतृत्व वाला विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग' विषय पर आधारित था। यह 9-12 मार्च तक चला। मंत्री ने गुरुवार को समापन सत्र के दौरान आईबीएसए फंड की सफलता और महिला सशक्तीकरण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को साझा किया।

सावित्री ठाकुर ने बताया कि आईबीएसए की ओर से 2004 में स्थापित आईबीएसए कोष आज दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। इस फंड ने अब तक लगभग 40 देशों में 50 से अधिक विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया है। ये परियोजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व और उनकी सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित हैं जो भारत के 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' के विजन को वैश्विक स्तर पर ले जा रही हैं।

मंत्री ने आईबीएसए ढांचे के तहत चल रही दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया। इनमें लाइबेरिया, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और विधायी स्तर पर महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही परियोजना है और दूसरी जॉर्डन शामिल है। जॉर्डन के तहत अपशिष्ट जल को रीसायकिल कर 60 ग्रीनहाउस और 50 महिला सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। इससे 150 महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।

श्रीलंका 84 ईरानी नाविकों के शव ईरान भेजेगा, 32 बचाए गए नाविक फिलहाल नहीं लौटेंगे

कोलंबो ■ एजेंसी

श्रीलंका ने अमेरिकी हमले में मारे गए 84 ईरानी नाविकों के शव ईरान वापस भेजने की घोषणा की है। ये सभी नाविक 4 मार्च को अमेरिका की तरफ से ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर हुए टॉरपीडो हमले में मारे गए थे। हमले के बाद राहत अभियान के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बचाए गए 32 ईरानी नाविक फिलहाल श्रीलंका में ही रहेंगे। शवों को ईरान द्वारा भेजे गए चार्टर्ड विमान से भेजे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

श्रीलंका के समाचार पत्र डेली मिरर के मुताबिक श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह उन 84 ईरानी नाविकों के शव ईरान वापस भेज रहा है, जिनकी मौत नौ दिन पहले एक हमले में हो गई थी। यह हमला तब हुआ जब ईरान का युद्धपोत आइरिस डेना श्रीलंका के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में यात्रा कर रहा था और उस पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉरपीडो दागे जाने से वह डूब गया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थुशारा रोड्रिगो ने बताया कि शवों को ईरान द्वारा भेजे गए चार्टर्ड कार्गो विमान से ले जाया जाएगा। इस प्रक्रिया से जुड़ी सभी घरेलू औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं।

हमले के तत्काल बाद श्रीलंकाई नौसेना ने 32 ईरानी नाविकों को बचा लिया था, जिन्हें फिलहाल श्रीलंका में ही रखा गया है। घायल नाविकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 22 को अब छुट्टी दे दी गई है। उन्हें द्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक वायुसेना अड्डे पर रखा गया है।

घटना गत 4 मार्च की है, जब ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना पर श्रीलंका के तट के पास टॉरपीडो से हमला हुआ। इस घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी निंदा हुई थी क्योंकि इससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष हिंद महासागर क्षेत्र तक फैलने का डर बन गया था। हमले के एक दिन बाद एक अन्य ईरानी युद्धपोत आइरिस बुशहर को श्रीलंका के जलक्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। श्रीलंका इस जहाज और उसके 219 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित आश्रय दे रहा है।

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरंभ बांग्लादेश सरकार से की हिंदुओं के संरक्षण की मांग

नई दिल्ली ■ एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज हरियाणा के समालखा में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान सरकार्यवाह की ओर से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संघ ने बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अपने यहां हिंदुओं के अधिकारों का संरक्षण करे।

शुरुआती सत्रों में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से आए सुधार और मणिपुर में संघ के प्रयासों से आए परिणाम का स्वागत किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार से एक बार फिर आग्रह किया गया कि हिंदुओं के अधिकारों का वहां संरक्षण होना चाहिए।

प्रतिनिधि सभा के प्रारंभ के बाद यहां सह सरकार्यवाह सी आर मुकुंद ने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।

इस दौरान सी आर मुकुंद ने बताया कि सर कार्यवाह ने अपने प्रतिवेदन में यह जानकारी दी कि संघ के शताब्दी वर्ष में किए गए प्रयासों से 4000 स्थान पर 5000 से अधिक शाखाओं में वृद्धि हुई है। गृह संपर्क अभियान के तहत संघ के कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे हैं। तीन लाख से अधिक गांव में संघ के कार्यकर्ता गए हैं। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां संघ के कार्यकर्ता साम्यवादी विचारधारा, मुसलमानों और क्रिश्चियन परिवारों से भी मिले हैं। अकेले केरल में 55,000 से अधिक मुस्लिम और 54,000 से अधिक क्रिश्चियन परिवारों में संघ के कार्यकर्ता संघ और समाज से जुड़े विषय लेकर गए हैं। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के नाते 36,000 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। वहीं इस दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत की देश के चार महानगरों में व्याख्यान माला आयोजित की गई।

लखनऊ में दूसरे चरण के ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण व अगले चरणों के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा

आपरेशन सिंदूर से पाक को ऐसा सबक सिखाया कि भारत पर हमले की सोच भी नहीं सकता

लखनऊ ■ एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया कि वह फिर कभी उबर भी नहीं पाएगा। भारत की सेना पूरी तरह से सतर्क और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहती है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लखनऊ में दूसरे चरण के ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण और तीसरे व चौथे चरण के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। गोमती नदी के तट पर झूलेलाल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ का तेजी से विकास हो रहा है और डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं है। यहां ब्रह्मोस मिसाइल, एयरो स्पेस से संबंधित काम भी हो रहा है और यह शहर देश की सुरक्षा व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है।

पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि वे दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर सोचा तो वे इस बार के हमले से कभी उबर भी नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले हर मंसूबे को करारा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। इन्होंने माफियाओं को सही कर दिया, लेकिन बुलडोजर सिर्फ तोड़ने का ही नहीं बल्कि विकास की नयी जमीन भी तैयार करता है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर की यात्रा महज 35 से 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जा सकेंगे। मुझे लगा था कहीं यह यात्रा स्थगित ना हो जाए मगर वह यात्रा पर गए और वहीं वेशभूषा पहन कर गए और वही खान-पान रखा और जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त निवेश आया है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासन की जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, उसी जमीन से कब्जा हटाकर उसी पैसे का प्रोजेक्ट बनाया गया और इसमें शासन ने प्राधिकरण को पैसा नहीं दिया है।

इस्तांबुल/वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के भीषण होते सैन्य टकराव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन (सीवीएन-72) को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने अभी तक ईरान के दावे की पुष्टि नहीं की है।

फिल्म एक दिन में नजर आयेंगे जुनैद खान और साई पल्लवी

अभिनेता जुनैद खान और साई पल्लवी की आने वाली फिल्म एक दिन की चर्चा जोरों पर है। बुधवार को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में एक फॉर्च्यून बेल, यानी किस्मत की घंटी, दिखाई जाती है। इस घंटी के बारे में जुनैद खान का किरदार बताता है कि दुनिया भर के हारे हुए आशिक इस घंटी को बजाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। इसी दौरान उनकी नजर मीरा पर पड़ती है, जिसका किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं। मीरा को देखते ही जुनैद का किरदार उस फॉर्च्यून बेल से एक विश मांगता है कि काश मीरा मेरी हो जाए, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही। इसके बाद ट्रेलर में कहानी आगे बढ़ती है। जुनैद की मांगी हुई यह विश सच हो जाती है। अगले ही सीन में मीरा यानी साई पल्लवी जुनैद के साथ दिखाई देती हैं। दोनों के बीच कई रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं। एक सीन में साई पल्लवी जुनैद का जन्मदिन सेलिब्रेट करती नजर आती हैं। वह उन्हें केक पर लगी कैंडल बुझाने से पहले एक विश मांगने के लिए कहती हैं। इस पर जुनैद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उनकी तो विश पहले ही पूरी हो चुकी है।

इस तरह ट्रेलर के बीच में दोनों के बीच पनपते प्यार और उनकी केमिस्ट्री को खूबसूरती से दिखाया गया है। ट्रेलर में दिखाए गए लोकेशन्स फिल्म के रोमांटिक माहौल को और मजबूत बनाते हैं। कभी दोनों साथ घूमते नजर आते हैं, तो कभी खुशियों के छोटे-छोटे पल साझा करते हुए दिखाई देते हैं।

ट्रेलर में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक दिन का साथ भी किसी की जिंदगी में बड़ी याद बन सकता है। हालांकि कहानी में सब कुछ इतना आसान नहीं रहता और यहीं से ट्रेलर एक दर्दनाक मोड़ लेता है।

ट्रेलर के आखिरी हिस्से में कहानी अचानक गंभीर मोड़ ले लेती है। एक सीन में साई पल्लवी गुस्से में जुनैद को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने... इसके बाद दोनों के बीच की दर्दनाक दूरी को दिखाया जाता है। आखिर दोनों के बीच क्या हुआ, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इस सीन को देखने के बाद दर्शकों के मन में सवाल उठता है कि आखिर उस एक दिन में ऐसा क्या हुआ, जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी।

ट्रेलर के आखिर में साई पल्लवी का किरदार कहता है कि यह एक दिन उनकी जिंदगी के लिए हमेशा यादगार रहेगा।

अगर फिल्म के बारे में बात करें तो एक दिन एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है। इस फिल्म के जरिए साई पल्लवी पहली बार हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू कर रही हैं।एक दिन 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

बलिया पर फिल्म बनाएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी

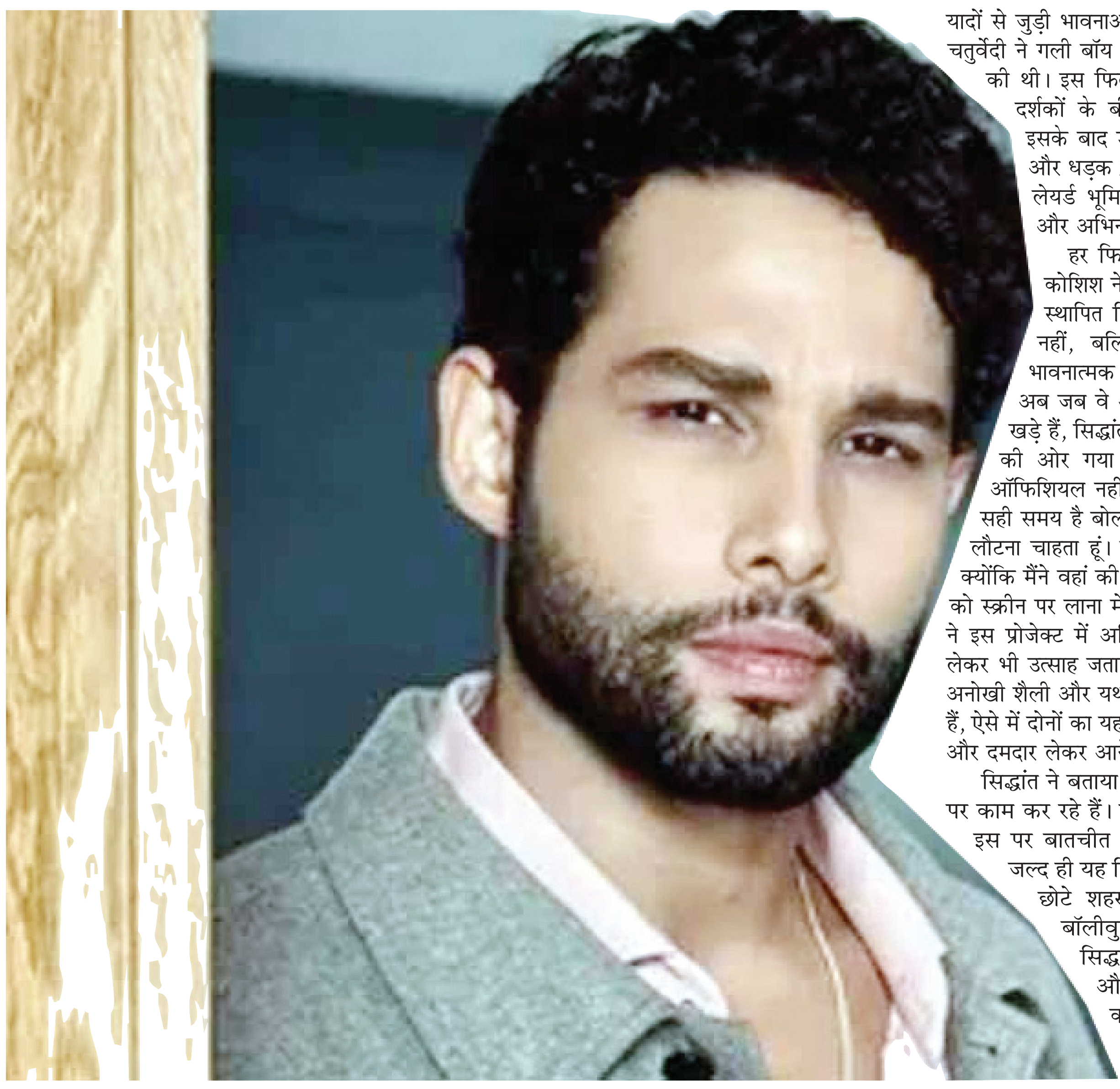

हाल ही में अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने खुलासा किया कि वे अपने करीबी दोस्त और फिल्मकार अभिषेक चौबे के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसकी कहानी पूरी तरह उनके होमटाउन बलिया पर आधारित होगी। यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक रचनात्मक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अपने जीवन, जड़ों और यादों से जुड़ी भावनाओं का सिनेमाई विस्तार है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने गली बॉय से बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें तुरंत दर्शकों के बीच एक मजबूत पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने गहराइयाँ, खो गए हम कहाँ और धड़क 2 जैसी फिल्मों में बेहद अलग और लेयर्ड भूमिकाएँ निभाईं, जिसमें उनकी पसंद और अभिनय की गहराई साफ दिखाई दी।

हर फिल्म में कुछ नया करने की उनकी कोशिश ने उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जो केवल स्टारडम के पीछे नहीं, बल्कि कहानियों की सच्चाई और भावनात्मक ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। अब जब वे अपने करियर के एक नए मोड़ पर खड़े हैं, सिद्धांत का झुकाव अपने जीवन की जड़ों की ओर गया है। उन्होंने कहा, 'अभी यह ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही समय है बोलने का। मैं अपनी रूट्स पर वापस लौटना चाहता हूं। मुझे बलिया की कहानी कहनी है, क्योंकि मैंने वहां की ज़िंदगी को जीया है। उन अनुभवों को स्क्रीन पर लाना मेरे लिए बेहद खास होगा।' सिद्धांत ने इस प्रोजेक्ट में अभिषेक चौबे के साथ सहयोग को लेकर भी उत्साह जताया। चौबे अपनी कहानी कहने की अनोखी शैली और यथार्थवादी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में दोनों का यह मिलन दर्शकों के लिए कुछ अलग और दमदार लेकर आने वाला है।

सिद्धांत ने बताया, 'हम एक बलिया-बेस्ड कहानी पर काम कर रहे हैं। यह वाकई कमाल की कहानी है। इस पर बातचीत जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यह फिल्म सबके सामने आएगी।' एक छोटे शहर के साधारण लड़के से लेकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने तक सिद्धांत का सफर मेहनत, विश्वास और संघर्ष से भरा रहा है। बलिया की गलियों, वहाँ के लोगों और वहाँ की मिट्टी से उनका गहरा लगाव अब उनके अगले प्रोजेक्ट का आधार बनने जा रहा है। उनके फैंस पहले ही जान चुके हैं कि सिद्धांत हमेशा ऐसे किरदार चुनते हैं जो कहानी की सच्चाई को सामने लाते हैं।

हॉरर-फैंटेसी 'तुम्बाड-2' में नजर आयेंगे नवाजुद्दीन

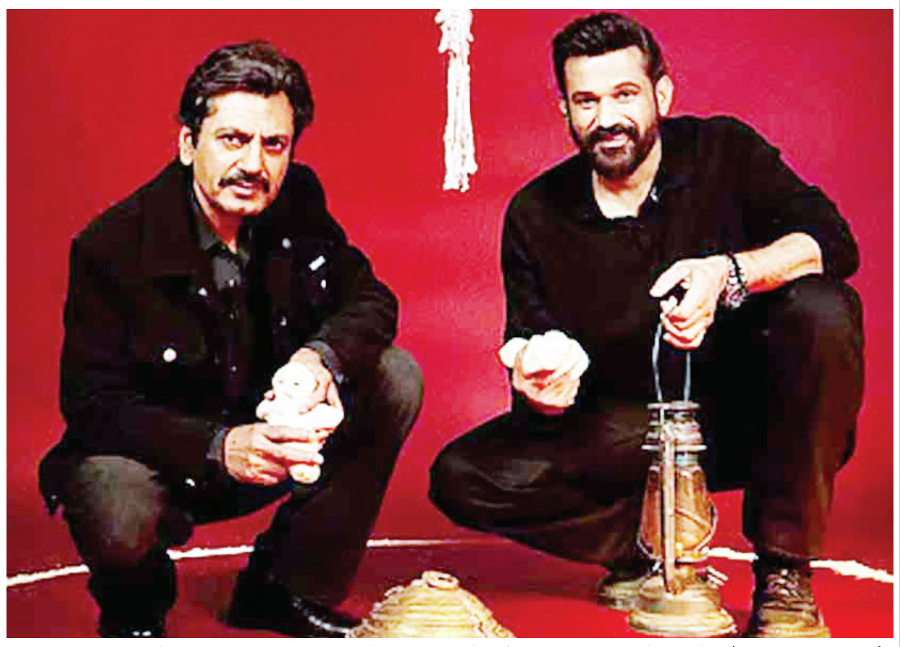

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कल्ट हॉरर-फैंटेसी फिल्म तुम्बाड के दूसरे सीजन में एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए शामिल किया गया है। दर्शकों को उम्मीद है कि यह सीक्वल पहले से कहीं अधिक रोमांचक और प्रभावशाली होगा। फिल्म के पहले भाग में विनायक राव की प्रमुख भूमिका निभाने वाले सोहम शाह ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार फोटो शेयर कर नवाजुद्दीन के जुड़ने की घोषणा की। फोटो में दोनों कलाकार रस्सी के सहारे मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

पोस्ट के जरिए सोहम ने लिखा, 'हमें खुशी है कि हमारे समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी 'तुम्बाड-2' से जुड़ गए हैं।' इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है, जो नवाजुद्दीन के किरदार और फिल्म की रिलीज़ डेट को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो अपने गहन और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल किरदारों के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में भी एक बेहद मजबूत और लेयर्ड भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि उनके किरदार की कहानी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी उपस्थिति सीक्वल के तनाव, रहस्य और हॉरर को कई गुना बढ़ा देगी। अभिनेता ने भी फिल्म का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि वे लंबे समय से 'तुम्बाड' की मौलिकता और उसके अनोखे माहौल की प्रशंसा करते रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जब सोहम शाह ने सीक्वल का विज़न साझा किया, तो कहानी ने उन्हें तुरंत आकर्षित किया और उन्होंने इस सफ़र में शामिल होने का फैसला कर लिया। नवाजुद्दीन ने यह भी कहा कि उनका किरदार कई परतों वाला है, जिसे निभाने के लिए वे बेहद उत्सुक हैं।

फिल्म का निर्माण पेन स्टूडियोज कर रहा है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स जल्द ही इसे फ्लोर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि तुम्बाड 2 अपने पहले भाग की तुलना में ज्यादा हॉरर, सस्पेंस और चौंकाने वाले मोड़ लेकर आएगी।

अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं अंकिता कोंवर और मिलिंद सोमन

मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता कोंवर अक्सर अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल, दोनों की उम्र में 26 साल का अंतर है, जिसके चलते शादी के बाद दोनों को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब दोनों की शादी को 13 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अंकिता ने एक खास पोस्ट के जरिए मिलिंद को सालगिरह की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 13 साल पहले, प्यार धीरे-धीरे मेरी जिंदगी में आया और वहीं ठहर गया। उसी प्यार ने मुश्किल वक्तों में, लंबी दूरी में, और उन दिनों में भी मेरा साथ दिया, जब सब कुछ बहुत भारी लगता था। उन्होंने आगे लिखा, तुमने मेरे हर रूप को अपनाया, मेरी ताकत को समझा और कमजोरियों को बहुत प्यार से संभाला। तुम मेरी हर जीत पर खुश हुए और उन चुनौतियों में भी मेरे साथ खड़े रहे, जो नामुमकिन लगती थीं। इन 13 सालों में बहुत सारी हंसी, बातें, तरक्की, माफी मांगना, रोमांच और वो प्यार रहा, जो हर दिन बदलता और मजबूत होता गया। खूबसूरत बात ये है कि आज भी मैं हर रोज इस प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं, जो हम दोनों साथ मिलकर जीते हैं। मिलिंद और अंकिता की जोड़ी फिटनेस, एडवेंचर और एक-दूसरे के प्रति गहरे सम्मान के लिए जानी जाती है। वे अक्सर साथ ट्रेकिंग करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं और जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीते हैं। मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर ने साल 2018 में शादी की थी उस वक्त मिलिंद की उम्र 52 और अंकिता की उम्र मात्र 26 साल थी। मिलिंद सोमन ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी लेकिन उन्हें पहचान फेमस पॉप सिंगर अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो से ही मिली थी। इसके बाद उन्होंने अभिनय की तरफ भी रुख किया। मिलिंद ने साल 2000 में आई फिल्म तरकीब की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी। इसके बाद वो दो साल तक फिल्मों से दूर रहे।

निक्की तंबोली ने रियलिटी शो से बाहर निकलने के बाद रखी अपनी बात

अभिनेत्री निक्की तंबोली रियलिटी शो द 50 से बाहर हो गई हैं। उन्हें डबल एविक्शन में शो से बाहर कर दिया गया। शो से निकलने के बाद निक्की ने सोशल मीडिया के जरिए शो में चल रहे संघर्ष और अपनी हालत के बारे में बात की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा और अपनी भावनाएं व संघर्ष साझा किए। निक्की ने लिखा, कई लोग कह रहे हैं कि जब अरबाज को शो से निकाला गया, तो मुझे भी शो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन शो में आने का मतलब जिम्मेदारी और वादा निभाना होता है। भावनाओं में आकर शो छोड़ना आसान लग सकता है पर कमिटमेंट निभाना असली हिम्मत है। निक्की ने लिखा कि जब मेरे भाई का देहांत हुआ था, तब भी मैं अगले दिन खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए गई थी। उन्होंने लिखा, मेरे लिए कमिटमेंट का मतलब यही होता है। भावनाएं सच्ची होती हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शो ने मुझे हमेशा सम्मान, महत्व और प्राथमिकता दी। कमिटमेंट सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि उस हिम्मत का नाम भी है, जब पता होता है कि बाहर लोग आलोचना करेंगे, कहानियां बनाएंगे, फिर भी आप मजबूत रहते हैं।

निक्की ने बताया कि शो में जाने से पहले वे डेंगू से ठीक होकर आई थीं। इसलिए ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने लिखा, कई लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस को जज किया, बिना जाने कि मैं डेंगू से ठीक होकर आई थी। शरीर में थकान, कमजोरी और बहुत ज्यादा थकावट थी। छोटी-छोटी चीजें भी भारी लगती थीं, फिर भी मैं हर दिन हिम्मत से शो में गई।उन्होंने कहा कि शो में उनका मुकाबला किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से था। उन्होंने कहा, मेरा असली मुकाबला किसी से नहीं बल्कि खुद से था।अपनी ताकत, सीमाओं और शरीर की लड़ाई से। सबसे कठिन लड़ाइयां अक्सर दिखाई नहीं देतीं। हर दिन वहां पहुंचना, थकान के बावजूद खड़े रहना और हार न मानना यही मेरी असली चुनौती थी।निक्की ने अपनी बात को खत्म करते हुए लिखा, अगर किसी को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं क्योंकि हर दिन मैं वहां जाकर खुद से लड़ रही थी। मेरी असली जीत यही थी कि शरीर हार मानना चाहता था, लेकिन मैं खड़ी रही और आगे बढ़ती रही।

आईसीसी ने टी20 विश्वकप विजेताओं पर की इनामों की बारिश, भारतीय टीम को मिले 24 करोड़

दुबई, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पुरुष टी20 विश्वकप 2026 के लिए इनामी राशि घोषित कर दी है। टूर्नामेंट में कुल 11.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब (1 अरब, 39 करोड़, 4 लाख, 43 हजार) की इनामी राशि दी गयी है। इस बार की इनामी राशि पिछली बार से अधिक है। इसमें विजेता भारतीय टीम को 2.63 मिलियन डॉलर करीब 24.3 करोड़ रुपये जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को 26,39,423 अमेरिकी करीब 13 करोड़ की इनामी राशि मिली है। वहीं सेमीफाइनल हारने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को 10,05,577 डॉलर करीब 9 करोड़ रुपये और इंग्लैंड की टीम को 9,74,423 डॉलर करीब 8 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं सुपरआठ की चार टीमों, वेस्टइंडीज को 5,38,269 डॉलर करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपये। वहीं पाकिस्तान 4,91,538 डॉलर करीब 4 करोड़ 80 लाख। जिम्बाब्वे को 4,91,538 डॉलर करीब 4 करोड़ 51 लाखा, श्रीलंका को 475,962 डॉलर करीब 4 करोड़ 37 लाख रुपये मिलेंगे। इस बीच, जो टीमें सुपर 8 स्टेज तक पहुंचीं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाईं, जिनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हैं, उनमें से प्रत्येक टीम को 3,09,808 डॉलर दिए जाएंगे। 2 करोड़ 85 लाख रुपये दिये जाएंगे।

अबरार पर काव्या मारन ने 2.34 करोड़ की बोली लगाई, बीसीसीआई उपाध्यक्ष बोले हमारा लेनादेना नहीं

भारतीय फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाक क्रिकेटर खरीदा

लंदन ■ एजेंसी

भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार को पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद पर बोली लगाई। सनराइजर्स की ष्टश्वह्र काव्या मारन ने खुद उन्हें 1.90 लाख पाउंड (करीब 2.34 करोड़ रुपए) में खरीदा। इसी के साथ अबरार 21 जुलाई से शुरू हो रही द हंड्रेड लीग में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी से जुड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए।अबरार को खरीदने पर सोशल मीडिया पर काव्या मारन की आलोचना की जा रही है। इस पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा- 'हमारे आईपीएल में इस तरह का कुछ नहीं है। हमारा अधिकार क्षेत्र आईपीएल तक आता है। बाहर किस लीग में कौन क्या कर रहा है उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? ये उनके ऊपर है कि वे क्या करते हैं। आईपीएल में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है।'

भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने 2009 के बाद से किसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन नहीं किया है। चेन्नई की मीडिया कंपनी सन ग्रुप ने पिछले साल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स में

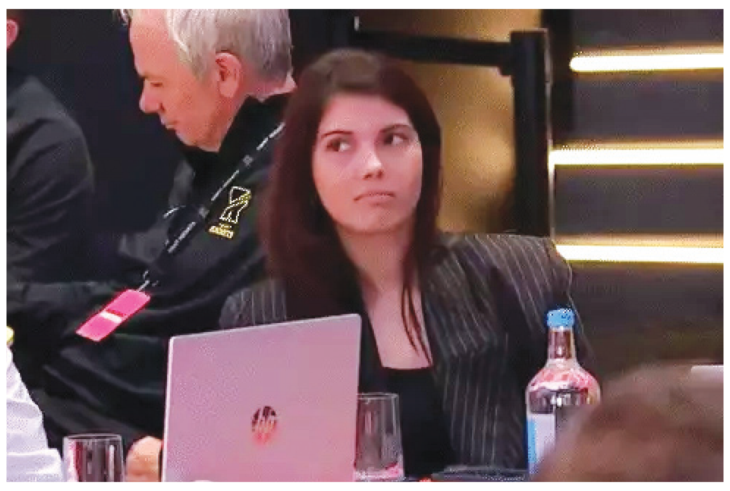

पहले 49% हिस्सेदारी ईसीबी से और बाकी 51% यॉर्कशायर काउंटी क्लब से करीब 10 करोड़ पाउंड में खरीदी थी। इसके बाद टीम का नाम बदलकर सनराइजर्स लीड्स रखा गया। सन ग्रुप आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप की भी मालिक है, लेकिन इन टीमों में अभी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है।

उस्तान तारिक 1.72 करोड़ रुपए में बिके: इस नीलामी में बिकने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक रहे, जिन्हें बर्मिंघम फीनिक्स ने 1.40 लाख पाउंड (लगभग 1.72 करोड़ रुपए) में खरीदा। हालांकि, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सैम अयूब अनसोल्ड रहे।

पाकिस्तान ने भारत से मैच का बॉयकॉट किया था: पाकिस्तानी सरकार ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि, श्रीलंकाई राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी सरकार ने भारत से मैच के लिए मंजूरी दी थी। कोलंबो में 15 फरवरी को खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने 61 रनों के अंतर से जीता था।

बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान पर विवाद हुआ था

आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के कारण भारत में इसका विरोध होने लगा। इस पर बीसीसीआई के कहने पर ऋचक्रने रहमान को रिलीज कर दिया है। इससे नाराज बांग्लादेशी सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत में टी-20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया था। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा के लिए मध्य प्रदेश की टीमें घोषित, खिलाड़ियों में उत्साह

इंदौर, निप्र। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन द्वारा आयोजित यूटीटी सीनियर नेशनल एवं अंतर-राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज 14 मार्च से इंदौर के ऐतिहासिक अभय प्रशाल में होने जा रहा है। 43 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शहर को मिली इस राष्ट्रीय मेजबानी को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। इस चैंपियनशिप में 34 राज्यों के लगभग 550 से अध?क खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और 20 लाख रुपये की इनामी राशि के लिए जोर आजमाइश करेंगे। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन की चयन समिति के अध्यक्ष ओम सोनी की अध्यक्षता में जयेश आचार्य, प्रमोद सोनी, रिंकू आचार्य और प्रमोद गंगराड़े की समिति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का गहन आकलन किया। चयन का आधार हाल ही में संपन्न हुई तीन राज्य रैंकिंग स्पर्धाएं और राज्य चैंपियनशिप रही है। मध्य प्रदेश की घोषित टीमें : पुरुष टीम : सौम्यदीप सरकार, शिवम सोलंकी (दोनों भोपाल), अनुज सोनी, प्रथम बाथम और पंकज विश्वकर्मा (तीनों इंदौर)। महिला टीम : मोमिता पाल, परिधि नागदेव (दोनों भोपाल), हिमानी चतुर्वेदी (ग्वालियर), भव्या राव और पूजा शर्मा (दोनों इंदौर)। टीम को मजबूती देने के लिए अजय राजपूत को प्रबंधक नियुक्त किया गया है, जबकि कलीम खान और साबिर अली को प्रशिक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अभय प्रशाल में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया।

2020 के मुकाबले भागीदारी दोगुनी, 15-24 उम्र की 16% लड़कियां खेल रहीं

भारतीय महिलाओं में क्रिकेट का क्रेज बढ़ा

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत में महिलाओं के बीच क्रिकेट खेलने की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक नए सर्वे के मुताबिक 2020 के बाद से 14 राज्यों में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हो गई है। बीबीसी और कलेक्टिव न्यूजरूम की ओर से कराए गए इस सर्वे में 10 हजार से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि 2020 में जहां सिर्फ 5% महिलाओं ने क्रिकेट खेलने की बात कही थी, अब यह आंकड़ा बढ़कर 10% हो गया है।

क्रिकेट को करियर चुन रहीं: युवा महिलाओं में बढ़ोतरी और तेज है। 15 से 24 साल की 16% लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 6% था। इसी उम्र वर्ग की हर चार में से एक लड़की ने खेल को करियर विकल्प के रूप में सोचने की बात भी कही है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रभाव छोड़ा: रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हाल की सफलताओं का भी असर दिख रहा है। टीम ने हाल ही में अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया को तीन मैच की टी-20 सीरीज में हराया।

सर्वे में यह भी सामने आया कि महिलाओं के बीच क्रिकेट अब पारंपरिक खेल कबड्डी से काफी आगे निकल गया है। 2020 में दोनों खेलों के बीच अंतर कम था, लेकिन अब क्रिकेट आगे है।

यूपी में 10% महिलाएं क्रिकेट खेल रहीं: ज्यादातर राज्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में तो यह आंकड़ा 1% से बढ़कर 10% तक पहुंच गया है। साथ ही पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच का अंतर भी कम हुआ है। अब हर एक महिला खिलाड़ी पर तीन पुरुष खिलाड़ी हैं, जबकि 2020 में यह अनुपात एक के मुकाबले पांच था। करियर के रूप में खेल को देखने वाली 15-24 उम्र की 26% लड़कियां हैं, जो 2020 में 16% थीं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 27%, मध्य प्रदेश और मेघालय में 19-19% दर्ज किया गया।

पंजाब में बैडमिंटन में महिलाएं आगे: सर्वे में यह भी बताया गया कि बैडमिंटन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, खासकर पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं अब भी एक बड़ी बाधा हैं। जो महिलाएं कोई खेल नहीं खेलतीं, उनमें से 13% ने सुरक्षा को वजह बताया।

भारतीय विमेंस ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता: भारत ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराते हुए विमेंस वर्ल्डकप में अपना पहला टाइटल जीता था। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वालीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था।

बीसीसीआई ने आईपीएल टीमों के प्रैक्टिस सेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके अनुसार कोई भी टीम उस नेट या पिच पर प्रैक्टिस नहीं कर सकेगी, जिस पर दूसरी टीम पहले अभ्यास कर चुकी हो। हर टीम को अभ्यास के लिए अलग और नए नेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

एलएन यूनिवर्स स्पोर्ट्स फैस्ट में बटे ढेरों पुरस्कार विजेताओं को मिली ट्रॉफी मेडल

भोपाल ■ निसं

एलएन यूनिवर्स स्पोर्ट्स फैस्ट जो कि पिछले 15 दिनों से एलएनसीटी विश्वविद्यालय में चल रहा था उसका पुरस्कार वितरण समारोह आज सीएमई हाल में संपन्न हुआ डॉ अनुपम चौकसे कुलाधिपति जेएनसीटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी,डॉ धर्मेंद्र गुप्ता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, डॉ अजीत कुमार सोनी रजिस्ट्रार, ए के सिंघई,डॉ विवेक श्रीवास्तव,डॉ तोषी व्यास, डॉ मुकेश साहू एवं पंकज कुमार जैन, डॉ पी एस दारा ने पुरस्कार बांटे शतरंज पुरुष वर्ग में चिराग दुबे फार्मेसी प्रथम सार्थक बावरिया स्कूल आफ लीगल स्टडी द्वितीय रहे महिला वर्ग में अनुष्का पाठक एलएन आयुर्वेद प्रथम,खुशबू युवराज चौधरी एलएन पैरामेडिकल द्वितीय रही

कैरम में पुरुष वर्ग में हर्ष द्विवेदी स्कूल आफ फार्मेसी प्रथम, दक्ष शिंदे स्कूल का लीगल स्टडी द्वितीय रहे वहीं महिला वर्ग में जेसिका दांगी आयुर्वेद प्रथम, प्रेरणा शुक्ला एल एन नर्सिंग द्वितीय रही टेबल टेनिस पुरुष वर्ग में स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन प्रथम रहा स्कूल आफ लीगल स्टडी द्वितीय स्थान पर रहा बैडमिंटन पुरुष वर्ग में स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन प्रथम एवं एलएन मेडिकल कॉलेज द्वितीय स्थान पर रहा वहीं महिला वर्ग में जेके पैरामेडिकल प्रथम स्थान पर स्कूल आफ आयुर्वेद दूसरे स्थान पर रहा वॉलीबॉल के मुकाबले में स्कूल आफ लीगल स्टडी प्रथम स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन महिला वर्ग में आयुर्वेद प्रथम स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन द्वितीय रहा रस्सा कसी के मुकाबले में आयुर्वेद कॉलेज ने महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि जेके पैरामेडिकल और महिला वर्ग में एलएन पैरामेडिकल द्वितीय स्थान पर रहा क्रिकेट में पिछले वर्ष की विजेता स्कूल आफ लीगल स्टडी प्रथम स्थान पर और स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन द्वितीय स्थान पर रहा महिला वर्ग में स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन प्रथम स्थान पर और एलएन नर्सिंग द्वितीय स्थान पर रहा फूटसल में स्कूल आफ फिजिकल एजुकेशन पुरुष एवं महिला दोनों में चैंपियन रहा जबकि आयुर्वेद पुरुष वर्ग में और जेके पैरामेडिकल महिला वर्ग में द्वितीय स्थान पर रहा टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार जैन ने बताया कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स फैस्ट एलएन यूनिवर्स कराया जाता है।

व्यापार समाचार

वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी: सीतारमण बोलीं

सरकार ने बनाया एक लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण फंड

नई दिल्ली ■ एजेंसी

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष बनाया, जो भारत को वैश्विक चुनौतियों से पैदा होने वाले आर्थिक झटकों से निपटने में मदद करेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.81 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा से अनुमति मांगी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड) सरकार को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद देगा। लोकसभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह फंड पश्चिम एशिया जैसी जगहों पर अचानक पैदा होने वाली समस्याओं से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले झटकों को संभालने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा, एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड भारत को वैश्विक परिस्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वित्तीय गुंजाइश देगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.81 लाख

करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति लोकसभा से मांगी है। लेकिन सरकार को 80 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आय भी मिलने की उम्मीद है। इसलिए इन दोनों को मिलाने के बाद सरकार को वास्तव में 2.01 लाख करोड़ रुपये ही अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।

सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) में राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान (आरई) के भीतर ही रहेगा। 2025-26 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसदी आंका गया है, जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है।

सीतारमण ने कहा कि दूसरी पूरक मांगों के कारण 2025-26 के बजट अनुमान से अधिक खर्च नहीं बढ़ा है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य एलपीजी की कमी के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी करते रहे। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में सरकार ने कुल खर्च को 50.65 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 49.65 लाख करोड़ रुपये कर दिया था।

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी तक सरकार 36.90 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी। सरकार ने पूरक अनुदान मांगों में एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, उर्वरक सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 23,641 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी गई है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के लिए 41,822 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का भी प्रस्ताव रखा गया है। सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी और अनुदानों की पूरक मांगों में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

जॉन डियर पावर एंड टेक्नोलॉजी ने भारत में 5एम सीरीज का 5130रू ट्रैक्टर पेश किया

नई दिल्ली ■ एजेंसी

डियर एंड कंपनी कृषि, निर्माण और वानिकी क्षेत्रों में एक वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर है, जो अपने ग्राहकों, चैनल भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। जॉन डियर लगातार एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में इन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

भारत में पिछले 27 वर्षों से अधिक समय से जॉन डियर खेती-किसानी के लिए तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रदान करता आ रहा है। इन समाधानों का उद्देश्य खेती की उत्पादकता बढ़ाना है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन जैसे टिकाऊ खेती के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी मजबूत करना है।

जॉन डियर इंडिया के एमडी और कंट्री मैनेजर और सीएंडएफ वर्ल्डवाइड प्रेसिडेंट के स्ट्रैटेजिक एडवाजइर राजेश सिन्हा ने कहा, 'जॉन डियर की रणनीति का मुख्य आधार सटीक खेती और स्मार्ट कनेक्टेड मशीनों के लिए डिजिटल समाधानों का एकीकरण है, जिससे किसान कम संसाधनों में अधिक उत्पादन कर सकें। हाल ही में पेश की गई तकनीकें खेतों के कामकाज को बेहतर बनाने और लागत को कम करने के साथ-साथ मिट्टी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित की गई

हैं।' उन्होंने आगे कहा कि भारत में जॉन डियर की उपस्थिति काफी व्यापक है और यह आरएंडडी, इंजीनियरिंग, ग्लोबल आईटी, सप्लाई चेन, सड़क निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग सहित कई क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस अवसर पर रमाकांत गर्ग, सेल्स एवं मार्केटिंग इंडिया डायरेक्टर ने कहा, 'उन्नत कृषि तकनीक और बदलती कृषि पद्धतियाँ एक-दूसरे के साथ चलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जॉन डियर भविष्य की कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप इन दोनों को एक साथ लाने के लिए प्रतिबद्ध है।'पावर एंड टेक्नोलॉजी 7.0' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के तहत कई नई तकनीकें और समाधान पेश किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जॉन डियर पहले भी भारतीय बाजार के लिए तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद पेश करता रहा है और आज के इस टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में भी कंपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियां तेजी से बदल रहीं पोर्टफोलियो

नई दिल्ली। सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआईएस) बाहरी दबावों के कारण मुख्य रूप से परिसंपत्ति गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक-राजनीतिक माहौल और राज्यों के कड़े नियम जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, असम और कर्नाटक में जबरन वसूली पर रोक ने इन संस्थानों को अपनी रणनीतियों में बदलाव के लिए प्रेरित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कुल परिसंपत्तियों पर 60 प्रतिशत तक पात्रता मानदंड में ढील देने के बाद, सूक्ष्म वित्त संस्थान अब सुरक्षित ऋण उत्पादों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इन उत्पादों में स्वर्ण ऋण, गृह सुधार ऋण, वाहन ऋण और संपत्ति के बदले ऋण शामिल हैं। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सैटिन क्रेडिटकेयर, स्पंदना स्फूर्ति जैसी संस्थाओं ने अपने पारंपरिक सूक्ष्म ऋणों में कमी की है। यह कदम जोखिम कम करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।

राजस्थान खान विभाग का मार्च में 1,500 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य

जयपुर। राजस्थान के खान विभाग ने मार्च महीने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित किया। विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने समीक्षा बैठक लेकर फील्ड अधिकारियों को लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति का निर्देश दिया। 10 मार्च तक विभाग ने 9,135 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि से 936 करोड़ रुपये अधिक है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी संग्रह में बेहतर वृद्धि रही। फरवरी में 1,060 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड संग्रह हुआ। रविकांत ने बताया कि आगामी दिनों के लिए खाका तैयार कर सभी फील्ड अधिकारियों के साथ साझा कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा खनिज वाहनों की जांच पर तुरंत सूचना मिलने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वाहनों के पास वैध परमिट और अनुमत मात्रा सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने वैकल्पिक उपाय किए लागू

एलपीजी की कमी से घरों में फिर लौट आया केरोसिन

नई दिल्ली ■ एजेंसी

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच तनाव ने वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत विदेशों से खरीदता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई बाधित होने के कारण घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर असर पड़ा। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी, जिससे होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति कम हो गई।

सरकार ने गैस की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाया। होटल और रेस्तरां को कोयला और बायोमास जलाने की अस्थायी छूट मिली, जबकि घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन का अतिरिक्त कोटा जारी किया गया। राज्यों को नियमित कोटे के ऊपर 48,000 किलोलीटर मिट्टी का तेल दिया गया। एलपीजी की कमी की अफवाहों के कारण बुकिंग में उछाल आया। इसे रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी वाले सिलेंडर की अगली बुकिंग अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 45 दिन की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह सीमा 25 दिन रखी गई। वर्तमान में देश में एलपीजी की डिलीवरी का औसत समय 2.5 दिन है और घरेलू उत्पादन में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केरोसिन कभी हर घर में उपयोग होता था, लेकिन 2013-14 से 2022-23 के बीच इसके उपयोग में सालाना 26 प्रतिशत गिरावट आई। बिजली, सोलर पैनल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ ऊर्जा नीति इसके मुख्य कारण रहे। दिल्ली 2014 में केरोसिन-मुक्त शहर घोषित हुआ। मार्च 2026 में केरोसिन की कीमतें 46-90 रुपये प्रति लीटर रही, औद्योगिक ग्रेड की कीमत प्राय: अधिक है।

केनस्टार लाया भारत के पहले 5-स्टार बीईई रेटेड एयर कूलर, अब मिलेगी कम बिजली में दमदार कूलिंग

गुरुग्राम ■ एजेंसी

केनस्टार, जो पिछले 30 सालों से भारत के भरोसेमंद होम अप्लायंस ब्रांड्स में से एक है, ने बिजली की बचत और कूलिंग के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने भारत के पहले 5-स्टार बीईई रेटेड एयर कूलर लॉन्च किए हैं, जिन पर 5 साल की पक्की वारंटी दी जा रही है। इस नई शुरुआत के साथ केनस्टार ऐसा पहला ब्रांड बन गया है जो सर्टिफाइड बिजली बचत को लंबी वारंटी के भरोसे के साथ जोड़ रहा है। इससे ग्राहकों को कम बिजली बिल, दमदार परफॉरमेंस और लंबे समय तक चलने वाली कूलिंग का फायदा मिलेगा।

लॉन्च के साथ ही केनस्टार ने एक खास कैंपेन भी शुरू किया है, जिसमें बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव और पत्रलेखा नज़र आ रहे हैं। इस कैंपेन के जरिए 'भारत का पहला 5-स्टार और 5 साल की वारंटी' का मैसेज बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। केनस्टार के 50 से ज्यादा एयर कूलर मॉडल्स घरों से लेकर दुकानों और ऑफिसों तक, हर जगह के लिए फिट हैं। कंपनी का वादा साफ है-हर जगह के लिए सही कूलिंग, वो भी बिजली की बचत और परफॉरमेंस से समझौता किए बिना। इन कूलरों में तकनीक है जो कम बिजली में ज्यादा हवा देती है। क्वाड्रा

फ्लो तकनीक हवा को चारों तरफ फैलाती है, जबकि हाइड्रो डेंस मेश हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स ठंडी और ताजी हवा देते हैं। साथ ही, इसकी मजबूत डबल बॉल बेयरिंग मोटर लंबे समय तक बिना रुके काम करती है।

लॉन्च के मौके पर केनस्टार के सीईओ सुनील जैन ने कहा, 'हमारे लिए इनोवेशन का मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। हमारी नई रेंज में बेहतरीन परफॉरमेंस, बिजली की सबसे ज्यादा बचत और लंबे समय का भरोसा-सब एक साथ मिलता है। यह लॉन्च दिखाता है कि हम भारतीय घरों को सही मायनों में उच?च गुणवत?ता और वैल्यू देना चाहते हैं।' यह कैंपेन केनस्टार को एक ऐसे ब्रांड के रूप में और मजबूत बनाता है, जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। आसान कहानियों के जरिए कंपनी अपने बिजली बचाने वाले कूलिंग के वादे को सीधे लोगों तक पहुँचा रही है। केनस्टार के ब्रांड एंबेसडर राजकुमार राव ने कहा, 'केनस्टार हमेशा से भरोसे का नाम रहा है। यह रेंज सिर्फ एक विज्ञापन नहीं, बल्कि एक वादा है जो बिजली की बचत और लंबे समय तक चलने वाले भरोसे के जरिए भारतीय परिवारों को असली फायदा पहुँचाता है।' अभिनेत्री और ब्रांड एंबेसडर पत्रलेखा ने कहा, 'केनस्टार की सबसे अच्छी बात वो भरोसा है ।

केरल में एलपीजी संकट से रेस्तरां और कैटरिंग सेवाएं ठप

कोच्चि। केरल में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण एलपीजी की कमी ने खाने-पीने के उद्योग को प्रभावित किया है। केरल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार, राज्य में लगभग 40 फीसदी रेस्तरां बंद होने की स्थिति बन रही है। शहरी क्षेत्रों के होटल और रेस्तरां सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि वहां लकड़ी या अन्य ईंधन से खाना बनाना व्यावहारिक नहीं है। प्राइवेट एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें दोगुनी तक पहुंच गई हैं।

प्रस्तावित गाइड लाईन वर्ष 2026-27 के संबंध में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित

रायसेन। जिले के अचल सम्पत्ति (भूखण्ड कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तावित गाइड लाईन वर्ष 2026-27 की दरों के निर्धारण हेतु कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति जिला रायसेन की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें जिले की प्रचलित गाइड लाईन की कुल 2296 लोकेशन में से 1344 लोकेशन में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई। शेष 952 लोकेशन में कोई मूल्य वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, वरिष्ठ जिला पंजीयक तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जल संचय के कार्यो में जनभागीदारी बढ़ाएं, नागरिकों को बताएं जल संचय का महत्व- कलेक्टर

कलेक्टर ने जल संचय जनभागीदारी अभियान की समीक्षा कर दिए दिशा-निर्देश

रायसेन ■ निसं

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में जल संचय जनभागीदारी अभियान के तहत जल संरचनाओं के निर्माण सहित किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। उन्होंने ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों तथा वनभूमि में जल संचय हेतु किए जा रहे कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने तथा जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यो पर भी चर्चा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी, डीएफओ श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय भी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर विश्वकर्मा ने पीएचई विभाग, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा तथा उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को जल संचय जनभागीदारी अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्य कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संचय के कार्यो में आमजन को भी जोड़ा जाए तथा जनभागीदारी से कार्य कराएं। बारिश के अधिक से अधिक जल को संरक्षित करने के लिए सोखपिट, रिचार्ज पिट निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

कलेक्टर विश्वकर्मा ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को प्राथमिकता से जल संचय जनभागीदारी अभियान के कार्यो की मॉनीटरिंग करते हुए शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने जिला, ब्लॉक, तहसील सहित ग्राम स्तर तक के कार्यालयों में जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं है, वहां निर्माण सुनिश्चित करें। साथ ही नागरिकों को भी अपने घरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के लिए जागरूक किया जाए। कलेक्टर विश्वकर्मा ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार या आवश्यकतानुसार मरम्मत और साफ-सफाई कराने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही नवीन जल संरचनाओं के निर्माण हेतु स्थलों का चयन और कार्ययोजना तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीएचई विभाग, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा तथा उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

चना, मसूर और सरसों के उपार्जन हेतु अंतिम तिथि के पहले पंजीयन कराने की अपील

रायसेन। रबी उपार्जन वर्ष 2025-26 अंतर्गत चना एवं मसूर फसल उपार्जन हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं तथा पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित है। साथ ही भावांतर योजना अंतर्गत सरसों फसल हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन भी 26 फरवरी से प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 निर्धारित हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के पंजीयन हेतु बनाए गए 117 निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर ही चना, मसूर, सरसों का पंजीयन किया जा रहा है। इन केन्द्रों के अतिरिक्त किसान ग्राम पंचायत कार्यालयों, जनपद स्तरीय कार्यालयों, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर निःशुल्क तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर सशुल्क व्यवस्था अनुसार पंजीयन करा सकते हैं। किसानों से निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराने की अपील की गई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो देख एसडीम ने संज्ञान में लिया मामला

रायसेन। जिले के गौहरगंज एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने बताया कि मंडीदीप में वृद्ध माताजी का वीडियो सोशल मीडिया से संज्ञान में आने पर जानकारी ली गयी। वीडियो में वृद्ध माताजी गाय के चारे से सामग्री उठाकर पॉलिथीन में रख रही हैं, इनके पुत्र श्री धन सिंह मालवीय वन विभाग चिकलोद रेंज में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ हैं। डिप्टी रेंजर ने अवगत कराया है कि मोनी के साथ रहती है वह उनका पूरा ध्यान रखते हैं उनका परिवार वार्ड नंबर 12 मंडीदीप में रहता है। धनसिंह ने यह भी अवगत कराया कि उनकी माताजी श्रीमती सरजू बाई उम्र लगभग 90 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं होने से कभी-कभी वह घर से बगैर बताए बाहर चली जाती हैं। इसी अवस्था के कारण संभवतः उक्त वीडियो की घटना घटित हुई है। वे उनके परिजनों को भेज कर तत्काल ही उन्हें घर लेकर आ रहे हैं उनका परिवार पूरी तरह उनकी माताजी की देखभाल और सेवा करता है।

महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, योजनाओं की जानकारी दी व स्वच्छता की शपथ दिलाई

विदिशा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विदिशा में आईटीसी मिशन सुनहरा कल एवं सीपा- समर्थ इन पार्टिसिपेटरी एक्शन सोसायटी, एनसीएचएसई द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वच्छता, कृषि एवं आजीविका से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी महिला सदस्यों को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

उमरागंज पुलिस की मानवीय पहल: गुमशुदा वृद्ध को सकुशल परिजनों से मिलाया

पुलिस ने एक गुमशुदा वृद्ध व्यक्ति को सकुशल खोजकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया

रायसेन ■ निसं

12 मार्च को डायल 112 पर इवेंट प्राप्त हुआ कि ग्राम अजवाइन में एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठे हुए हैं, जो अपना सही परिचय नहीं बता पा रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक 386 सुनील पठारिया एवं पायलट ओमप्रकाश तत्काल मौके पर पहुंचे।

मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने देखा कि लगभग 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति सहमा और डरा हुआ बैठा हुआ था। पुलिस द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पहले वृद्ध व्यक्ति के लिए भोजन एवं पानी की व्यवस्था कराई गई तथा उन्हें शांत कराकर बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उनसे मिली

जानकारी के आधार पर उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया।

पूछताछ में वृद्ध व्यक्ति का नाम बाबूलाल भालसे पिता खुशियाल भालसे उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पाडल्या थाना पिपलोद जिला खंडवा* होना ज्ञात हुआ। जानकारी में यह भी सामने आया कि वे अपनी पोती के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपने पुत्र पन्नालाल भालसे निवासी मुक्तिधाम बांसखेड़ी कोलार भोपाल के घर आए हुए थे, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण रास्ता भटक कर ग्राम अजवाइन पहुंच गए थे।

पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने पर उनके पुत्र पन्नालाल भालसे थाना उमरागंज पहुंचे, जिनके समक्ष गुमशुदा बाबूलाल भालसे को सकुशल उनके सुपुर्द किया गया।

अपने पिता को सुरक्षित पाकर पन्नालाल भालसे ने रायसेन पुलिस का आभार व्यक्त किया। साथ ही ग्राम अजवाइन के नागरिकों द्वारा भी पुलिस की इस मानवीय कार्यवाही की सराहना की गई।

अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

रायसेन, निप्र। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी बेगमगंज श्रीमती सोनाली गुप्ता के नेतृत्व में थाना गैरतगंज पुलिस को अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 25 लाख रुपये कीमती मशरूका बरामद किया गया है। 28 फरवरी को फरियादी गौरव सोनी पिता रामबाबू सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी किसानी मोहल्ला गैरतगंज ने थाना गैरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रामजानकी मार्केट स्थित उसकी सोने-चांदी की दुकान से पांच अज्ञात महिलाएं सोने के आभूषणों से भरा एक बॉक्स चोरी कर ले गई हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर

थाना गैरतगंज में अपराध क्रमांक XX/26 धारा 305(ए) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी गैरतगंज डी.पी. लोहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र में लगे करीब 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए तथा महिलाओं के आने-जाने के रास्तों की तस्दीक की गई। प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम को राजस्थान रवाना किया गया।

पुलिस टीम द्वारा जिला बारां (राजस्थान) में कार्रवाई करते हुए दिनांक 12 मार्च को घटना में प्रयुक्त होंडा अमेज कार (कीमत लगभग 05 लाख रुपये) तथा करीब 120 ग्राम सोने के आभूषण (कीमत लगभग 20 लाख रुपये) आरोपी भरत बागरी से जप्त किए गए। घटना में शामिल अन्य पांच महिला आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देना है अनिवार्य, सूचना नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

रायसेन ■ निसं

निर्माण कार्य की जानकारी देकर श्रमिक कल्याण में दें अपना योगदान

श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों पर सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप पर निर्माण स्थल का पंजीयन विवरण, कर्मचारियों की संख्या, स्थान (लोकेशन) सहित अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है, जिस पर नियोजक श्रमिकों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे सकते है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के प्रावधानों अनुसार किसी भवन या अन्य सनिर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व उस क्षेत्र में, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सनिर्माण कार्य किया जाना है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को स्थल, सुरक्षा उपाय सहित समस्त आवश्यक जानकारी साँझा करना अनिवार्य है। निर्माण स्थलों की जानकारी या सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है। सूचना न देने पर निरीक्षण के दौरान नियम उल्लंघन माना जा सकता है और नियोक्ता पर जुर्माना / कार्रवाई भी हो सकती है। अधिनियम के प्रावधानो अनुसार यदि कोई नियोजक, धारा 46 के अधीन भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ की सूचना नहीं देता है, तो उसे कारावास; जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी या जुर्माना; जो दो हजार रुपए तक अथवा दोनों हो सकता है।

कंट्रोल रूम नंबर 18002338888 पर करें शिकायत या दें जानकारी: विभाग ने यह भी कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण स्थल की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम नंबर-18002338888 पर भी सम्पर्क कर सकते है। निर्माण कार्य का पंजीयन नहीं किये जाने पर नागरिक इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी देकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

जिले में शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार ही उपार्जन कार्य सम्पादित किया जाए- कलेक्टर

रायसेन ■ निसं

रबी विपणन उपार्जन हेतु समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा सर्वेयर को दिया गया प्रशिक्षण

वन परिसर में शुक्रवार को कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूँ उपार्जन हेतु जिले में प्रस्तावित 190 उपार्जन केन्द्रों के लिए समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं गुणवत्ता नियंत्रकों सर्वेयर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा गुणवत्ता नियंत्रकों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति एवं अन्य निर्देशों का अक्षरतः पालन करते हुए उपार्जन कार्य सम्पादित किया जाए। सभी समिति प्रबंधकों को उपार्जन संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां भी उपार्जन प्रारंभ होने के पहले पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा पोर्टल संबंधी एवं गुणवत्ता प्रशिक्षणकों द्वारा गुणवत्ता संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उपार्जन कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाने एवं शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार खरीदी संबंधी समस्त कार्य, ऑनलाईन प्रविष्टि आदि निर्धारित दिन व समय पर किए जाने के बारे में जानकारी दी गई।

धारा 126 के प्रकरणों में छूट प्राप्त करने का मौका, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन करें आवेदन

रायसेन ■ निसं

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन 01 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्वीक लिंक टैब में 126 पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के पोर्टल पर कंज्यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही उपभोक्ता को धारा-126 में दर्ज लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्त किए जाने हेतु 'उपभोक्ता के परिसर या अन्य परिसर पर संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है न ही निर्णित है' सत्यापित कर सबमिट करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चयन कर भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑफलाइन आवेदन हेतु उपभोक्ताओं के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को दिया जाकर, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो। कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत यदि एक संयोजन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं तो एक साथ सभी प्रकरणों का भुगतान एक मुश्त किया जाना अनिवार्य है।

सीएम लाडली बहना योजना जिले की 2.71 लाख महिलाओं के खातों में 40 करोड़ रुपये की राशि अंतरित

विदिशा ■ निसं

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव-भितरवार से योजना की लाभार्थी महिलाओं के खातों में मार्च 2026 की किस्त की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदिशा जिले की कुल 2 लाख 71 हजार 312 लाडली बहनों के बैंक खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि सीधे अंतरित की गई है।

जिले में विभिन्न विकासखंडों और नगरीय निकायों की लाभार्थी महिलाओं के खातों में भी राशि पहुंची है। इसमें जनपद पंचायत गंजबासौदा की 40,475, ग्यारसपुर की 24,308, कुरवाई की 27,306, लटेरी की 25,551, नटेरन की 33,167, सिरोंज की 36,583 तथा विदिशा की 29,327 महिलाओं को योजना का लाभ मिला। वहीं नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका गंजबासौदा की 11,951, नगरपालिका सिरोंज की 8,744, नगरपालिका विदिशा की 25,543, नगर परिषद कुरवाई की 2,991, लटेरी की 3,337 तथा शमशाबाद की 2,029 महिलाओं के खातों में भी राशि अंतरित की गई।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत मुख्यालयों पर लाडली बहनों को दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी भी दी गई।

यूजीसी बिल के समर्थन में आज विशाल रैली, दशहरा मैदान से निकलेगी पदयात्रा

विभिन्न संगठनों ने की अधिक संख्या में शामिल होने की अपील

रायसेन ■ निसं

यूजीसी बिल के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांगों को लेकर ओबीसी-एसटी-एससी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में कल 14 मार्च को रायसेन में विशाल रैली और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे दशहरा मैदान में समाज के लोगों के एकत्रित होने के साथ होगी, जिसके बाद सुबह 11 बजे रैली निकाली जाएगी।

रैली दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर भोपाल रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने से होते हुए महामाया चौक, मुख्य बाजार मार्ग से गुजरते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी। यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रायसेन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया

कि इस रैली में जिले भर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पिछले एक महीने से व्यापक स्तर पर तैयारियां और प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी प्रचार रथ के माध्यम से लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की गई है।

यह प्रमुख मांगें रहेंगी शामिल: यूजीसी बिल लागू किया जाए, जातीय जनगणना में ओ बी सी, एस टी, एस सी के लिए अलग कॉलम दिया जाए, 13% की सीमा हटाकर ओ बी सी को 27% आरक्षण दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल की जाए, किसानों के गेहूं का समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, सामाजिक संगठनों का समर्थन इस कार्यक्रम को विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। ओ बी सी, एस सी, एस टी के समाज संगठनों ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में रायसेन पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। यूजीसी बिल के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाएं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में रैली में शामिल हों।

कन्या महाविद्यालय में आयुष्मान कार्ड शिविर आयोजित, 85 छात्राओं के बने कार्ड

विदिशा ■ निसं

राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वाधान में छात्राओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बी.डी. अहिरवार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस प्रभारी डॉ. शांता अहिरवार द्वारा महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से छात्राओं को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान की गई। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी

डॉ. पुनीत माहेश्वरी के नेतृत्व में छह सदस्यीय आशा कार्यकर्ताओं की टीम ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस टीम में पिंकी जाटव, कविता रघुवंशी, सीमा शर्मा, उर्मिला भार्गव, भगवती विश्वकर्मा और प्रीति अहिरवार शामिल रहीं, जिन्होंने छात्राओं का पंजीयन कर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की। शिविर के दौरान महाविद्यालय की कुल 149 छात्राओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 85 छात्राओं के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाए गए। इस पहल से छात्राओं को शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी डी.पी.गोयल द्वारा आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सागर रोड, रायसेन से प्रकाशित तथा श्री बालाजी प्रिन्टर्स, 21-एच, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल- 462023 (म.प्र.) से मुद्रित।: संपादक- डी.पी.गोयल। मो.9827054436, 9826735596. व्यवस्थापक: श्याम अग्रवाल, भोपाल कार्यालय : 4240007. फैक्स:0755-4296195 (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।)।